PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

जुलाई 2022 / Issue-1

यूपीएससी और राज्य आधारित पीसीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगी

मुख्य परीक्षा विशेषज्ञ- भारतीय समाज, कला एवं संस्कृति, भारतीय इतिहास

- आईएमएफ के नजरिये से विश्व अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ
- समुद्री हीटवेव और भारत में चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति
- वैश्विक खाद्य संकट: कारण और समाधान
- पड़ोसी देशों में व्याप्त अस्थिरता और भारत पर प्रभाव
- अग्निपथ- सशस्त्र बलों को दक्ष एवं भविष्योन्मुखी बनाना
- दो टाइम जोन होने से भारत पर प्रभाव
- एफडीआई अनुमोदन को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®

most trusted since 2003

ALL INDIA UPSC MAIN TEST SERIES 2022

26th June 2022

COMPREHENSIVE UPPSC MAIN TEST SERIES 2022

26th June 2022

OPTIONAL SUBJECT MAIN TEST SERIES 2022

PSIR
26th June 2022

GEOGRAPHY
26th June 2022

PUBLIC ADMINISTRATION
3rd July 2022

FACE TO FACE CENTRES

Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474

Visit Website

UDAAN

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Think About IAS/IPS Just After 12th

IAS OLYMPIAD ENTRANCE EXAM-2022

24th JULY 2022 | 12:30 PM

For More Information :
www.dhyeyaudaan.in

UPTO 100% SCHOLARSHIP

Lucknow (Aliganj) : 7570009014, 9506256789 | Lucknow (Gomtinagar) : 7234000501, 7234000502

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

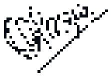

Q H Khan
Managing Director

प्रस्तावना

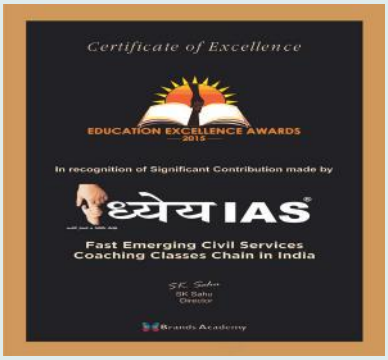

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है. आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय. परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है. इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है. एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिक. ाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी , अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है. शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा.

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी. इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें. हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा.

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

सपादक	:	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
सहसंपादक	:	गौतम तिवारी
उप-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
सहायक उप-संपादक	:	अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन	:	डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग	:	प्रशान्त सिंह
	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	शिव वरदान
	:	गौरव चौधरी
	:	देवेन्द्र सिंह
	:	लोकेश शुक्ला, प्रिंस
मुख्य लेखक	:	विवेक ओझा
मुख्य समीक्षक	:	ए.के. श्रीवास्तव
	:	विनीत अनुराग
	:	बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं	:	रविन्द्र पटेल
विकास	:	पुनीष जैन
टंकण	:	सचिन
	:	तरून
कार्यालय सहायक	:	राजू, चन्दन
	:	अरूण

साभार : PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना, कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिकी लेख 1-14

- आईएमएफ के नजरिये से विश्व अर्थव्यवस्था की चुनौतियां
- समुद्री हीटवेव और भारत में चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति
- वैश्विक खाद्य संकट: कारण और समाधान
- पड़ोसी देशों में व्याप्त अस्थिरता और भारत पर प्रभाव
- अग्निपथ- सशस्त्र बलों को दक्ष एवं भविष्योन्मुखी बनाना
- दो टाइम जोन होने से भारत पर प्रभाव
- एफडीआई अनुमोदन को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय 15-16
संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय 16-18
संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण 18-19
संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक 20-21
संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक 22-23
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें 24-27
समसामयिक घटनाएं एक नजर में 28
ब्रेन-बूस्टर 29-35
मुख्य परीक्षा विशेष 36-42
समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 43-44
व्यक्ति विशेष 45

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

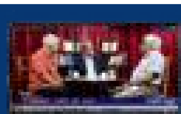

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

आईएमएफ के नजरिये से विश्व अर्थव्यवस्था की चुनौतियां

समाचार में क्यों

अप्रैल में विश्व आर्थिक आउटलुक ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास 2021 में अनुमानित 6.1 प्रतिशत से 2022 और 2023 में 3.6 प्रतिशत हो जाएगा। 2023 से परे, वैश्विक विकास में मध्यम अवधि में लगभग 3.3 प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान है ।

निकट अवधि के वैश्विक विकास के प्रभावित करने वाले कारक

- **यूक्रेन में युद्ध-** रूस का आक्रमण और परिणामी प्रतिबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। संघर्ष और प्रतिबंधों का प्रभाव सीधे यूक्रेन, रूस और बेलारूस पर पड़ रहा है। लेकिन वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, व्यापार और वित्तीय संबंधों में व्यवधान, श्रम आपूर्ति और मानवीय प्रभावों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्पिलओवर व्यापक रूप से प्रभाव फैलाएंगे मुख्यत: यूरोप में।
- **मौद्रिक सख्ती और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव-** युद्ध से पहले भी, मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई थी, और कई केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति को सख्त कर दिया था। इसने उन्नत अर्थव्यवस्था वाले संप्रभु उधारकर्ताओं में नाममात्र (Nominal) ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि का योगदान दिया। हाल के महीनों में, नीतिगत दरें आम तौर पर और बढ़ रही हैं, जैसा कि अमेरिका और भारत द्वारा किया गया है। सख्त नीति की उम्मीदों और युद्ध की चिंताओं ने वित्तीय बाजार में अस्थिरता और जोखिम पुनर्मूल्यां. कन में योगदान दिया है। विशेष रूप से, युद्ध और संबंधित प्रतिबंधों ने वैश्विक वित्तीय स्थितियों को सख्त कर दिया है, जोखिम की इच्छा कम कर दी है, और फ्लाइट-टू-. क्वालिटी प्रवाह को प्रेरित किया है। रूस में, प्रतिबंधों और घरेलू वित्तीय मध्यस्थता की हानि के कारण इसके संप्रभु और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप स्प्रेड में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **राजकोषीय निकासी-** कई देशों में 2020-21 में आवश्यक उच्च COVID-संबंधित खर्च और कम कर राजस्व से नीतिगत स्थान समाप्त हो गया था। बढ़ती उधारी लागतों का सामना करते हुए, सरकारों के बफर्स पुनर्निर्माण की अनिवार्यता के कारण चुनौती बढ़ती जा रही है। राजकोषीय समर्थन आम तौर पर 2022 और 2023 में गिरावट की ओर है - विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए आपातकालीन उपाय हटाए जा रहे है।
- **चीन की मंदी-** चीन की अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि का एशिया और कमोडि. टी निर्यातकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अधिक पारगम्य वेरिएंट और जीरो-COVID रणनीति का संयोजन चीन में निजी खपत पर प्रभाव के साथ, लगातार लॉकडाउन की संभावना पर जोर देता है। इसके अलावा, अत्यधिक लीवरेज्ड प्रॉपर्टी डेवलपर्स के प्रति सख्त रुख का मतलब है कि रियल एस्टेट निवेश मंद बना हुआ है।
- **महामारी और टीके तक पहुंच -** श्रमिकों की कमी और गतिशील प्रतिबंधों ने 2022 की शुरुआत में आपूर्ति में व्यवधान और अड़चनों को बढ़ा दिया, जिससे गति. विधि में बाधा उत्पन्न हुई और मुद्रास्फीति को बढ़ाया मिला। जैसे ही ओमिक्रॉन लहर कम हुई, प्रतिबंधों में ढील देना शुरू हो गया अन्तत: वैश्विक साप्ताहिक COVID मौतों में गिरावट आई है।

एशिया में विकास

शेष विश्व की तरह ही एशिया में भी आर्थिक संवृद्धि, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के आघात से प्रभावित हुआ। एशिया का रूस और यूक्रेन से अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष व्यापार और वित्तीय जोखिम रहा है। फिर भी, वस्तुओं की उच्च कीमतों और यूरोपीय व्यापारिक भागीदारों में धीमी वृद्धि से इन अर्थव्यवस्थाओं की पहुंच प्रभावित होगी।

एशिया में मुद्रास्फीति, जो महामारी के दौरान अपेक्षाकृत कम थी, खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद बढ़ने लगी है। युद्ध से झटका ऐसे समय आया है जब महामारी से उबरना भी मुश्किल था जब वैश्विक वित्तीय स्थिति सख्त होती जा रही है। नई COVID लहर कुछ देशों में, विशेष रूप से चीन में प्रतिकूल परिस्थितियो को शामिल कर रही हैं। चीन में कम विकास, कई एशियाई व्यापारिक भागीदारों को प्रभावित कर रहा है जो इससे एकीकृत हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक सख्ती एशिया में भी उच्च ब्याज दरों को बढ़ावा दे रही है, जिससे विकास पर और दबाव पड़ रहा है। ये प्रतिकूल परिस्थितियां महामारी के मध्यम अवधि के भयावह प्रभावों को इस क्षेत्र में कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ा सकती है। ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ ऐसे समय में आई हैं जब नीति पर प्रतिक्रिया देने की गुंजाइश कम है। नीति निर्माताओं को एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें वैश्विक वित्तीय स्थितियों और उच्च ऋण स्तरों के बीच बढ़ती मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपूर्ण पुन:निर्माण के बीच संतुलन बनाना होगा।

अप्रैल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, 2022 में एशियाई जीडीपी के 4.9 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जो जनवरी के

अपडेट से कम है। पिछले साल अन्य देशों की तुलना में बहुत कम होने के बाद एशिया में मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। 2022 में मुद्रास्फीति अब बढ़कर 3.4 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इसलिए, इस क्षेत्र को स्टैगफ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें विकास पहले की अपेक्षा कम है और मुद्रास्फीति अधिक है।

- चीन के लिए, अप्रैल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने 2022 के विकास पूर्वानुमान को जनवरी अपडेट में 4.8 प्रतिशत की तुलना में संशोधित कर 4.4 प्रतिशत कर दिया है। यह संशोधन यूक्रेन में युद्ध, स्थानीयकृत COVID प्रकोप और लॉकडाउन से एक बड़े नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। नीतिगत प्रोत्साहन का सकारात्मक प्रभाव आंशिक रूप से इन प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई करता है।
- भारत में, कठिन नीतिगत ट्रेडऑफ यूक्रेन युद्ध के नतीजों से स्पष्ट हैं, विशेष रूप से उच्च तेल कीमतों से चालू खाता घाटे में वृद्धि जिससे मुद्रास्फीति के बढ़ने की उम्मीद है। जबकि अप्रैल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार अभी भी विकास 8.2 प्रतिशत पर होने की संभावना है, यह जनवरी अपडेट की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम है।
- अप्रैल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने जापान में विकास को संशोधित कर 2.4 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 0.9 प्रतिशत अंक की गिरावट है। चीन की तरह, यह युद्ध के प्रभाव, यूरोप से स्पिलओवर और ओमिक्रोन लहर के अनुमान से अधिक प्रभाव को दर्शाता है। हाल ही में तेजी के बावजूद, मुद्रास्फीति कम बनी हुई है, जिससे बैंक ऑफ जापान, फेड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की तुलना में अधिक उदार (Accommodative) हो सकता है।
- अप्रैल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, दक्षिण-कोरिया में विकास, 2021 में 4 प्रतिशत से घटकर 2022 में 2.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो जनवरी अपडेट से 0.5 प्रतिशत अंक की गिरावट है। इस बीच, ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और घरेलू मांग के दबाव ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य से ऊपर धकेल दिया है।
- आसियान देशों के लिए, अप्रैल विश्व आर्थिक आउटलुक में 0.2 प्रतिशत अंक की गिरावट अन्य देशों की तुलना में कम है। यह इस क्षेत्र में कुछ कमोडिटी निर्यातकों के लिए व्यापार की अनुकूल शर्तों को दर्शाता है। हालाँकि, युद्ध मुद्रास्फीति के दबावों और सख्त वित्तीय स्थितियों को बढ़ा रहा है।
- श्रीलंका में, खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि और पर्यटन में कमी ने पहले से मौजूद कमजोरियों और ऋण स्थिरता दबावों को बढ़ा दिया है, जिससे सामाजिक अशांति

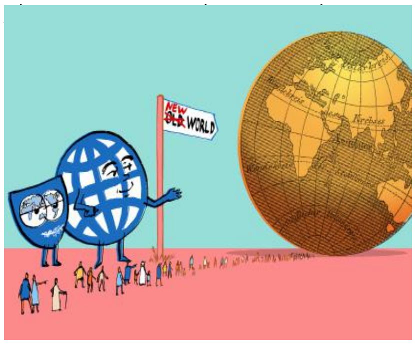

संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विकास

रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच आर्थिक संबंध सीमित हैं। अन्य कारक भी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पूर्वानुमान पहले से ही विश्व आर्थिक आउटलुक में अपने जनवरी अपडेट में कम किया गया था, जो मुख्य रूप से ब्यूल्ड बैक बेटर राज. कोषीय नीति पैकेज के पारित ना होने और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के जारी रहने को दर्शाता है। अप्रैल की रिपोर्ट में 2022 के लिए अतिरिक्त 0.3 प्रतिशत अंक पूर्वानुमान से कम करना, पिछले अनुमान की तुलना में मौद्रिक समर्थन की तेजी से वापसी को दर्शाता है।
- कनाडा के लिए पूर्वानुमान को अप्रैल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 0.2 प्रतिशत अंक नीचे चिह्नित किया गया है, जो नीति समर्थन की वापसी और संयुक्त राज्य अमे. रिका से कमजोर बाहरी मांग को दर्शाता है।

निष्कर्ष

मानवीय संकट होने के अलावा, यूक्रेन में युद्ध वैश्विक विकास पर भी भारी असर डाल रहा है। यूक्रेन और रूस से, आर्थिक प्रभाव तेजी से भारत सहित अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है।

NOTES

समुद्री हीटवेव और भारत में चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति

संदर्भ-
पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपि. कल मौसम विज्ञान के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन के अनुसार, हिंद महासागर में समुद्री गर्मी बढ़ रही है, जिससे भारतीय मानसूनी वर्षा और चक्रवातों पर प्रभाव पड़ रहा है।

परिचय-
अरब सागर के ऊपर विकसित होने वाले चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता पिछले दो दशकों में बढ़ी है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऐसे कम तूफान देखे गए हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री गर्मी की लहरें (MHW), जो समुद्र और महासागरों के तापमान में वृद्धि की अवधि हैं, पिछले कुछ दशकों में ये काफी बढ़ गई हैं। हाल के दशकों में, गर्म अरब सागर 'गंभीर' श्रेणियों के चक्रवातों का मंथन कर रहा है।

चक्रवात और समुद्री हीटवेव क्या है-
- चक्रवात एक बड़ा वायु द्रव्यमान है जो कम वायुमंडलीय दबाव वाले मजबूत केंद्र के चारों ओर उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमता है। चक्रवातों की विशेषता आवक-सर्पिल (Inward spiraling winds) हवाओं द्वारा होती है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास घूमती हैं।
- समुद्री हीटवेव असामान्य रूप से उच्च समुद्र के तापमान की अवधि है जोकि अवधि और तीव्रता से परिभाषित होती है। समुद्री सतह के तापमान के माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र के तापमान मापा जाता है। औसत समुद्री सतह के तापमान से विचलन को तापमान विसंगतियों के रूप में जाना जाता है।

हीट वेव्स के कारण-
- जैसा कि जेजीआर ओशन्स नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि हीट वेव्स की घटना भारतीय मानसून और चक्रवातों को प्रभावित कर रही है।
- समुद्री हीटवेव कारकों की एक पूरी श्रृंखला के कारण हो सकते हैं परन्तु सभी कारक प्रत्येक घटना के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। समुद्री हीटवेव के सबसे आम चालकों में महासागर धाराएं शामिल हैं जो गर्म पानी और वायु-समुद्री गर्मी प्रवाह के क्षेत्रों का निर्माण कर सकती हैं। हवाएं समुद्री हीटवेव में वार्मिंग को बढ़ा या दबा सकती हैं, और अल नीनो जैसे जलवायु मोड कुछ क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की संभावना को बदल सकते हैं।
- इस तरह की गर्मी की लहरें महासागरों की गर्मी खासकर ऊपरी परतों में वृद्धि के कारण होती हैं। दुनिया भर में, वे मानव-प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख परिणामों में से एक हैं। एक MHW के दौरान, समुद्र की सतह का औसत तापमान (300 फीट की गहराई तक) सामान्य से 5-7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाता है।
- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होने वाली गर्मी का लगभग 90 प्रतिशत महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार, वर्ष 2021 ने समुद्र की गर्मी के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे के रॉक्सी मैथ्यू कोल के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पाया गया कि हिंद महासागर में तेजी से गर्म होने और मजबूत अल नीनो घटनाओं के कारण समुद्री गर्मी की लहरों में वृद्धि हुई।

चक्रवात की बढ़ती आवृत्ति
- नए अध्ययन के अनुसार, 1982 और 2002 के बीच 19 साल की अवधि की तुलना में 2001 और 2019 के बीच अरब सागर के ऊपर चक्रवातों की आवृत्ति में 52% की वृद्धि देखी गई, और बंगाल की खाड़ी में 8% की कमी देखी गई। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के वैज्ञानिक के अनुसार आम तौर पर एक वर्ष में चार से पांच चक्रवात उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र (बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शामिल हैं) में बनते हैं, जिनमें से अधिकांश - लगभग तीन-चार - बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित होते हैं।
- लेकिन यह तेजी से बदल रहा है। उदाहरण के लिए, 2019 में उत्तर हिंद महासागर में आठ चक्रवात देखे गए, जिनमें से पांच अरब सागर में बनते हैं । 2018 के लिए कुल आंकड़ा सात था, जिसमें तीन अरब सागर के ऊपर बने थे।

हिंद महासागर में चक्रवातों पर समुद्री गर्मी की लहरों का प्रभाव-
- अध्ययन के अनुसार, हिंद महासागर में इसका पश्चिमी भाग और बंगाल की उत्तरी खाड़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। पश्चिम हिंद महासागर में समुद्री हीट वेव (MHWs) की संख्या में 1982 और 2018 के बीच प्रति दशक लगभग 1.5 घटनाओं की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में प्रति दशक लगभग 0.5 घटनाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
- हिंद महासागर में समुद्री गर्मी की लहरें भी दक्षिण-पश्चिम मानसून को प्रमुख रूप से प्रभावित कर रही हैं। जोकि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का प्रमुख कारण है।

- समुद्री हीट वेव से जुड़े उच्च पानी का तापमान उष्णकटिबंधीय तूफान और हरिकेन जैसी चरम मौसम की घटनाओं का कारण बन सकता है और जल चक्र को बाधित कर सकता है जिससे बाढ़, सूखा और जंगल की आग आदि के अधिक होने की संभावना है।
- हालिया रिपोर्ट के अनुसार, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में सुपर साइक्लोन अम्फान का कारण भी समुद्री हीटवेव रहा।
- जल के सर्वेक्षण से पता चला है कि मई 2020 में तमिलनाडु तट के पास मन्नार की खाड़ी में 85 प्रतिशत प्रवाल समुद्री गर्मी के बाद नष्ट हो गए।
- विश्लेषणों से पता चलता है कि इन वर्षों में अरब सागर में चक्रवातों की तीव्रता 20% से 40% तक बढ़ गई है। समुद्र की सतह का तापमान जो यहां चक्रवात का कारण बना, अब चार दशक पहले की तुलना में 1.2-1.5° C अधिक है।
- इसका मतलब है कि समुद्र तेजी से गर्म हो रहा है। यह गर्मी के प्रवाह को बढ़ाता है जोकि समुद्र से वायुमंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को महासागरों में सक्रिय करने में गर्मी (Heat) और नमी (Moisture) का बडा योगदान होता है।
- हाल के दशकों में, गर्म होता अरब सागर 'गंभीर' श्रेणियों के चक्रवातों से प्रभावित रहा है। महासागरों के गर्म होने के कारण मछली पकड़ने और मत्स्य उद्योग पर आधारित आजीविका भी लगातार खतरे में है।

चक्रवात का प्रभाव–

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र वृत्ताकार तूफान वाले होते हैं जो 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति और भारी बारिश के साथ गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होते हैं।
- इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में भी जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन जाते हैं। अलग. -अलग खतरे जो व्यक्तिगत रूप से जीवन और संपत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, उनमें तूफान, बाढ़, अत्यधिक हवाएं, बवंडर और लाइटेनिंग (बिजली गिरना) शामिल हैं।
- चक्रवात के निकल जाने के बाद भी तबाही रह जाती है। गिरे हुए पेड़ सड़कों को अवरुद्ध कर सकते हैं और चिकित्सा आपूर्ति के साथ बचाव में देरी कर सकते हैं, या बिजली की लाइनों, टेलीफोन टावरों या पानी के पाइप की मरम्मत को धीमा कर सकते हैं, जो अन्य जीवन को काफी दिनों के लिए जोखिम में डाल सकता है। रुका हुआ पानी बीमारी के प्रसार का कारण बन सकता है, और परिवहन या संचार के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकता है, सफाई और बचाव के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

निष्कर्ष–

समुद्री हीटवेव में स्पष्ट रूप से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को तबाह करने और मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर और इकोटूरिज्म उद्योगों में आर्थिक नुकसान को बढ़ाने की ताकत है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लू का प्रभाव भी तेज हो गया है।

जलवायु मॉडल के अनुमान भविष्य में हिंद महासागर के और अधिक गर्म होने का सुझाव देते हैं, जो बहुत अधिक संभावना है कि समुद्री हीटवेव और मानसून वर्षा पर उनके प्रभाव को तेज करेंगे। चूंकि समुद्री हीटवेव द्वारा कवर की गई आवृत्ति, तीव्रता और क्षेत्र बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इन घटनाओं की सटीक निगरानी करने के लिए अपने महासागर अवलोकन सारणियों को बढ़ाने की आवश्यकता है और उष्णीय (Warmign World) दुनिया द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का कुशलतापूर्वक अनुमान लगाने के लिए हमारे मौसम मॉडल को अपडेट करना होगा।

NOTES

वैश्विक खाद्य संकटः कारण और समाधान

संदर्भ-

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख ने चेतावनी दी थी कि रूस-यूक्रेन युद्ध से शुरू हुआ खाद्य संकट बिना किसी हस्तक्षेप के वर्षों तक बना रह सकता है।

परिचय-

महामारी के बाद भोजन की बढ़ती मांग, चरम मौसम की स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और निर्यात प्रतिबंधों ने खाद्य बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण ने दुनिया भर में खाद्य कीमतों में व्यापक मुद्रास्फीति बढ़ाया एवं खाद्य और कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सूचकांक को 1990 में शुरू होने के बाद से अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक न्गोजी ओकोन्जो-इवेला ने कहा कि वैश्विक खाद्य संकट पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा और अफ्रीकी देश, विशेष रूप से गेहूं और उर्वरक की कमी से और अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

वैश्विक खाद्य संकट का कारण-

- संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की रिपोर्ट भूख और खाद्य असुरक्षा में हालिया वृद्धि के प्रमुख कारकों की रूपरेखा तैयार करती है ये कारण हैं देशों के बीच संघर्ष, जलवायु परिवर्तनशीलता और आर्थिक मंदी (COVID-19 महामारी द्वारा तेज) आदि ।
- 2022 में दुनिया भर में खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि और खाद्य आपूर्ति की कमी देखी गई।
- दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जटिल संकट भू-राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक कारणों जैसे कि अत्यधिक गर्मी, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले सूखे के कारण हुए थे।
- जबकि महामारी के बाद की वैश्विक मांग, चरम मौसम, सख्त खाद्य भंडार, उच्च ऊर्जा की कीमतें, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं और निर्यात प्रतिबंध और कर दो वर्षों से खाद्य बाजार पर दबाव डाल रहे हैं, रूस के आक्रमण के बाद इन सभी कारकों का हालिया अभिसरण अभूतपूर्व है और दुनिया भर में खाद्य मुद्रास्फीति की दर में तेजी आई है।
- विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख के अनुसार गेहूं की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 59% की वृद्धि हुई, सूरजमुखी के तेल में 30% की वृद्धि हुई, जबकि मक्का में 23% की वृद्धि हुई।
- रूस और यूक्रेन से वैश्विक कृषि निर्यात को युद्ध ने बाधित कर दिया है, दोनों देश मूल्य के अनुसार वैश्विक गेहूं निर्यात का 24%, सूरजमुखी के बीज के तेल के निर्यात का 57% और 2016 से 2020 तक मकई का 14% निर्यात करते हैं ।
- यूक्रेन में युद्ध होने से दुनिया में खाद्य अनाज में ही नहीं बल्कि उर्वरकों की कमी कर दी। रूस और बेलारूस संयुक्त रूप से, दुनिया के पोटाश के निर्यात का लगभग 40% सहयोग करता है, रूस ने अकेले दुनिया के 11% यूरिया और 48% अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात किया था। रूस और यूक्रेन मिलकर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साथ-साथ पोटेशियम से बने 28% उर्वरकों का निर्यात करते हैं। उर्वरक संकट कुछ मायनों में खाद्य उत्पादन को बाधित कर सकता है और वैश्विक खाद्य संकट को और बढ़ा सकता है।

खाद्य संकट का वैश्विक प्रभाव -

- खाद्य संकट पर 2022 की वैश्विक रिपोर्ट का अनुमान है कि इस वर्ष 41 देशों और क्षेत्रों में लगभग 180 मिलियन लोग खाद्य संकट में होंगे।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पूर्वी अफ्रीकी देश में लगातार सूखे के कारण लगभग 13 मिलियन लोग गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं।
- यूक्रेन दुनिया भर के देशों को बड़ी मात्रा में अनाज का निर्यात करता है, एशिया और अफ्रीका इसके प्राथमिक खरीदार हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के अनुसार, कम विकसित देशों सहित 25 अफ्रीकी राष्ट्र, दो युद्धरत देशों से अपने एक तिहाई से अधिक गेहूं का आयात करते हैं। उनमें से 15 देश 50% से अधिक आयात रूस और यूक्रेन से करते है। इसके अलावा, यूक्रेन विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के लिए 50% अनाज की आपूर्ति करता है, जो दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से 125 मिलियन लोगों की भूख मिटाता है।
- लगभग 20 देशों ने फरवरी 2022 से खाद्य प्रतिबंध और उन पर कर लगाए हैं, जिससे विश्व स्तर पर भोजन की कमी हो रही है।
- कुछ देशों की कृषि को भी जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ा जैसे दक्षिण अमेरिकी देश, अर्जेंटीना, सोयाबीन, मक्का और मांस का एक प्रमुख उत्पादक है, इस साल की शुरुआत में हीटवेव के कारण खराब फसल हुई थी। भारत के गेहूं के उत्पादन में भी गर्मी की लहरों के कारण गिरावट आई है।
- जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का खाद्य उत्पादन 16% गिर सकता है और 2030 तक भूख के जोखिम वाले लोगों की संख्या 23% बढ़ सकती है।

खाद्य पर्याप्तता में भारत की स्थिति-

- भारत ने हरित क्रांति के बाद से खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारी प्रगति की है।
- 2020 में, भारत ने 300 मिलियन टन से अधिक अनाज का उत्पादन किया और 100 मिलियन टन का खाद्य भंडार बनाया था।
- 2021 में, भारत ने रिकॉर्ड 20 मिलियन टन चावल और गेहूं का निर्यात किया।
- 30 अप्रैल, 2022 तक केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 30.3 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष के 52.5 मिलियन टन से बहुत कम था, लेकिन बफर स्टॉक मानदंडों से अधिक था।

समाधान-

- वैश्विक खाद्य और भूख की समस्याओं को हल करने के लिए विश्व को व्यापार के खुले प्रवाह को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए, जिस पर हर देश अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए निर्भर करता है। व्यापार बाधाएं और निर्यात प्रतिबंध सभी पक्षों के लिए हानिकारक हैं, और विशेष रूप से संकट के समय में सभी देशों को साथ मिल कर चलना चाहिए। हाल ही में G7 बैठक में सभी देशों ने ''अपने भोजन और कृषि बाजारों को खुला रखने'' का आह्वान किया। यह कदम और दृढ़ होना चाहिए ।
- विश्व के अन्य क्षेत्रों में उचित रूप से उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही बिना किसी देरी के रूस और यूक्रेन को खाद्य उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। यू.एस और यूरोप, जैव ईंधन (ऊर्जा के लिए) के उपयोग में आने वाली भूमि को भोजन के लिए फसलों के उत्पादन के लिए उपयोग में लाना चाहिए। वर्तमान में, अमेरिका में उगाए गए मकई का एक तिहाई और यूरोपीय संघ में उगाए गए 3-4 मिलियन टन गेहूं ईंधन के लिए इथेनॉल का उत्पादन करते हैं, जबकि अमेरि. की सोयाबीन और यूरोपीय रेपसीड का एक बड़ा हिस्सा बायोडीजल के लिए उपयोग किया जाता है।
- सभी देशों को डेटा साझा करने, राष्ट्रीय भंडार और अन्न भंडार से कब और किन परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों को निकालना है? इसका पता लगाने के लिए अच्छे विश्वास के साथ मिलकर काम करना चाहिए। खाद्य और पोषण सुरक्षा में राष्ट्रीय भंडार की अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका होती है; खाद्य पदार्थों की कीमतों को कम करने और मानवीय संकटों को कम करने के लिए इनका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है।
- यूक्रेन पर आक्रमण से पहले प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की रिपोर्ट, इन चुनौतियों से निपटने के लिए खाद्य प्रणालियों को बदलने के छह तरीकों की सिफारिश करती है और ''सभी के लिए, स्थायी और समावेशी रूप से सस्ती स्वस्थ आहार तक पहुंच सुनिश्चित करती है''।
- सक्षम देशों को दुनिया भर के सबसे गरीब समुदायों जैसे उप-सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व को इस संकट से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा तैयार करना होगा। इसमें ऋण राहत ; नकद हस्तांतरण कार्यक्रम; ऋण योजनाएं, बाजारों और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सहित छोटे किसानों को समर्थन में वृद्धि; ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश; और सबसे कमजोर राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और लचीलेपन के साथ सहायता करने के लिए समर्थन का एक बड़ा पैकेज शामिल है।
- यूक्रेनी अनाज निर्यात को फिर से शुरू करने के प्रयास में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वह रूस, यूक्रेन, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ ''लगातार संपर्क'' में हैं।

निष्कर्ष-

बढ़ती खाद्य कीमतों रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध और जलवायु परिवर्तन आदि खाद्य संकट में योगदान दे रहा है। कई देशों ने घोषणा की कि निर्यात प्रतिबंध के उपाय स्थिति को खराब कर रहे हैं। यह वह समय है जब हर देश को खाद्य असुरक्षित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने और वहां उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहल करनी चाहिए। अमेरिका जैसे देशों को जैव ईंधन की तुलना में खाद्यान्न पर ध्यान देना चाहिए। यूक्रेनी सरकार ने वैश्विक बाजार चुनौतियों से निपटने के लिए सात देशों के समूह (जी 7) देशों को अनाज निर्यातक देशों का एक प्रभावशाली संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया है क्योंकि यूक्रेन विश्व स्तर पर खाद्यान्न के प्रमुख आपूर्तिकर्ता में से एक है।

NOTES

पड़ोसी देशों में व्याप्त अस्थिरता और भारत पर प्रभाव

सन्दर्भ

पिछले कुछ समय से वैश्विक पटल पर काफी उथल पुथल का माहौल रहा है फिर चाहे वह शरणार्थी समस्या हो, आर्थिक समस्या, कोविड–19 महामारी, रूस–यूक्रेन युद्ध, पश्चिम–पूर्व में प्रतिस्पर्धा, नियम–आधारित विश्व व्यवस्था को न मानना या फिर राजनीतिक अस्थिरता हो, ऐसे समय में विकासशील देशों के लिए समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। यह केवल भारत के पडोसी देशों में ही नहीं देखने को मिलता है बल्कि कई अन्य देशों में भी हुआ है।

पाकिस्तान

पाकिस्तान छद्म युद्ध का सहारा 1947 से ले रहा है जिसके कारण भारत के साथ कई युद्ध हुए परंतु 1990 आते – आते जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का प्रभाव तेजी से दिखायी पड़ने लगा। 1990 के बाद भारत में हुए सीरियल ब्लास्ट, संसद हमला, मुंबई हमला, पठानकोट, उरी और पुलवामा आदि का तार पाकिस्तान से ही जुडा रहा है। पाकिस्तान की 23 करोड़ जनता के लिए वहां कभी विकास कार्य नहीं हुआ। यही कारण रहा कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है वही राजनीतिक अस्थिरता से पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। अप्रैल में इमरान खान का सत्ता से बेदखल होने से वहां गृहयुद्ध जैसे स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इससे उनकी धरती पर पनप रहे आतंकवादियों का मनोबल बढा।

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान हमेशा से बड़ी शक्तियों के हाथों में खेलता रहा। सन 1979 ई. के बाद में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सेना ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहा ताकि अमेरिकी वर्चस्व को अपनी सीमा से दूर रखा जा सके परंतु इसका परिणाम उल्टा रहा और तालिबान जैसे कट्टर संगठन का उदय हुआ। वर्तमान समय में अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्से में तालिबान का कब्जा है जबकि कई सेक्शन तालिबान के खिलाफ भी हैं जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविन्स प्रमुख है।

म्यांमार

राजनीतिक अस्थिरता का कुछ ऐसा ही उदाहरण म्यांमार में देखने को मिलता है जहां सत्ता का संघर्ष जनता द्वारा चुनी सरकार और जुंटा सरकार(सैन्य सरकार) के बीच रहा है। रखाइन प्रान्त से पलायन करने को मजबूर हुए रोहिंग्याओं ने भारत और बांग्लादेश में शरण ले रखी है। इससे म्यांमार के ऊपर कई प्रकार का प्रतिबन्ध लगा हुआ है। फूड क्राइसिस से लेकर कोरोना महामारी तक सभी ने वहां की आम जनता को प्रश्रय मांगने हेतु मजबूर किया है।

श्रीलंका

श्रीलंका हिन्द महासागर में अपनी भू-राजनीतिक स्थिति के कारण आकर्षण का केंद्र रहा है। राजनीतिक उठा पटक जिसमें तमिल और सिंहली समूह के बीच अविश्वास से देश में अस्थिरता व्याप्त रही है, राजपक्षे परिवार ने अपनी नीतियों से श्रीलंका को दिवालिया बना दिया। उन्होंने श्रीलंका की धरती का प्रयोग भारत के खिलाफ करने में गुरेज नही किया और चीन की पहुंच मोतियों की माला वाली नीति के तहत श्रीलंका में हो सकी। उसने कर्ज और सहायता के नाम पर श्रीलंका को खोखला बना दिया। आज श्रीलंका इस तरह से डेब्ट ट्रैप में फंस गया है कि उसको ब्याज भुगतान के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। पिछले दो महीने में सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर आ गए और महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। इस स्थिति में भारत ने 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट तो दिया ही है साथ में खाद्य सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई है।

नेपाल

यह उन देशों में शामिल है जिसका भारत के साथ सम्बन्ध एकदम पारिवारिक एवं घनिष्ठ रहा है। भारत हमेशा नेपाली लोगों के बेहतरी के लिए प्रयासरत रहा है। 1949 ई. से लेकर अभी तक इसने 7 संविधानों को अपनाया है फिर भी किसी प्रधानमंत्री ने सम्पूर्ण कार्यकाल पूरा नही किया। 2015 ई. में जब भूकंप आया, भारत उन कुछ देशों में था जिसने विभिन्न प्रकार की राहत सामग्री पहुंचायी थी। जब से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया विशेषकर केपी शर्मा ओली ने अपना रुख चीन की ओर ज्यादा रखा ताकि भारत से निर्भरता कम की जा सके। चीन के लोक लुभावन कर्ज से नेपाल की स्थिति भी दयनीय होती जा रही है। वहां चीनी राजदूत नेपाल के राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं जिससे भारतीय हितों को नुकसान होता ही है साथ में खुले बॉर्डर पर खतरा बढ़ जाता है।

मालदीव

हिन्द महासागर में स्थित मालदीव का भारत से अच्छा संबंध रहा है लेकिन संबंधों में खटास तब बढ़ गयी जब वहां की अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने भारत विरोधी तत्वों को समर्थन देना शुरू कर दिया। मालदीव चीन

के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बन गया परन्तु जब से मोहम्मद सो. लिह की सरकार बनी, भारत से पुनः संबंध अच्छे हुए हैं। फिर भी वहां पर कट्टर तत्वों ने बीच -2 में भारत विरोधी अभियानों को बल प्रदान किया है जिससे भारत के समुद्री सीमा को सचेत रहने पर मजबूर किया है।

बांग्लादेश और भूटानः दिखाते परिपक्वता

बांग्लादेश और भूटान ने आर्थिक विकास और स्वतंत्र नीति पर जोर देकर बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि चुनौतियां वहां भी आयी लेकिन उन्होंने उसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया। बांग्लादेश ने शेख हसीना के शासन में एक तरफ इस्लामिक कट्टरता को कमजोर करने का प्रयास किया वही दूसरी ओर विकास को सर्वोपरि रखा है जिसका परिणाम यह हुआ कि बांग्लादेश सूती वस्त्रो के निर्माण, मत्स्यन, कृषि उत्पाद आदि के क्षेत्र में भारत को चुनौती दे रहा है। वही भूटान जोकि स्थलरुद्ध देश है फिर भी अपने लोगों के विकास और आवश्यकताआ. ें की पूर्ति के लिए बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। भूटान ने पर्यावरण संरक्षण और उसके साथ जीने का अच्छा तालमेल बनाया है। आज भूटान और बांग्लादेश दोनों की मानव विकास सूचकांक में भारत से बेहतर रैंकिंग है। कम संसाधन होने के बावजूद इन देशों ने नीतियाँ बनाते समय जो परिपक्वता दिखाई है वह अन्य देशों के लिए उदाहरण है। इन देशों ने चीन की नीतियों को बहुत नजदीक से अनुभव किया है।

भारत पर प्रभाव

अगर पड़ोस के देशों में अस्थिरता रहेगी तो इससे भारत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जैसे- यदि पाकिस्तान और अफगानिस. तान में अस्थिर सरकार होगी और वहां की सेना या अन्य समाज विरोधी तत्व सक्रिय हुए तो इससे भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर विशेषकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में प्रभाव पड़ेगा जिससे भारत को रक्षा बजट बढ़ाना होगा। वही यदि नेपाल और म्यांमार में अस्थिरता होगी तो भारत में शरणार्थी समस्या तो बढ़ेगी ही साथ में भारत की 3400 किमी. से भी अधिक चीन के साथ सीमा सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जायेगा। ये देश भारत के लिए एक रक्षा कवच की भूमिका में स्थित हैं। यदि श्रीलंका और मालदीव में राजनीतिक हलचल बढ़ी तो इससे भारत के लिए कई तरह से खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे- भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा करने में चुनौती, अधिकतर व्यापार समुद्र के रास्ते होता है जिसमें आये दिन पायरेसी की घटना घटित होती रही है, अगर इन देशों में स्थिर सरकार नहीं रही और इन देशों की नेवी का सहयोग नहीं मिला तो समुद्री व्यापार के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है जिसमें सबसे प्रमुख समस्या होगी चीन का हिन्द महासागर में प्रभाव। इन सबसे भारत के विकास में बाधा उत्पन्न होगी, आन्तरिक असुरक्षा उत्पन्न होगा, अन्य बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप बढेगा, अपने लोगों के विकास में फंड का प्रयोग न करके रक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ाना होगा जोकि राजकोषीय घाटा को बढ़ाएगा। अतः भारत को पड़ोसी देशों में स्थिरता की स्थापना हेतु पूरा प्रयास करना चाहिए ।

आगे की राह

भारत दुनिया के उन पांच देशों में से है जिसकी अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन अमेरि. की डॉलर से ज्यादा है। दुनिया के टॉप-20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की आर्थिक संवृद्धि सबसे तेज है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने पड़ोसी देशों की अधिक से अधिक मदद करे। भारत को 'पड़ोसी प्रथम' एवं गुजराल डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिये।उनके यहाँ की लोकतान्त्रिक संस्थाओं की मजबूती और सरकारों की स्थिरता हेतु अपना बेस्ट अनुभव शेयर करें ताकि आर्थिक सम्पन्नता होने से लोगों का लिविंग स्टैण्डर्ड बढे और क्षेत्र में खुशहाली आये।

NOTES

अग्निपथ- सशस्त्र बलों को दक्ष एवं भविष्योन्मुखी बनाना

समाचार में क्यों

हाल ही में सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है। भारत के कुछ हिस्सों में इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

अग्निपथ योजना- विवरण

- इस योजना में अधिकारी रैंक से नीचे पदों के लिए एक भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें फिट, युवा सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में तैनात किया जाएगा, जिनमें से कई चार साल के अनुबंध पर होंगे।
- सभी तीन सेवाओं में एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसके बाद विशिष्ट रैलियां और परिसर साक्षात्कार, मान्यता प्राप्त तकनीकी कॉलेजों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क द्वारा आयोजित किए जाएंगे। नामांकन 'ऑल इंडिया ऑल क्लास' के आधार पर होगा, जिसकी पात्र आयु 17.5 से 21 के बीच होगी (जिसे प्रारम्भ में 23 वर्ष रखा गया है)। अग्निवीर सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे जो उनकी विशेष श्रेणियों/व्यापारों पर लागू होते हैं। अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता कई श्रेणियों में नामांकन के लिए एक मानदंड बनी रहेगी, जैसे कि सामान्य ड्यूटी (जीडी) सैनिक बनने के लिए शैक्षणिक आवश्यकता कक्षा 10 है।
- इस योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ रुपये 30,000/- प्रति माह का अग्निवीर पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा, जोखिम और कठिनाई, पोशाक और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
- पहली अग्निपथ प्रवेश भर्ती रैली सितंबर-अक्टूबर 2022 से शुरू होगी।
- चार साल की सेवा के बाद, 25% अग्निवीरो को योग्यता, इच्छा और चिकित्सा फिटनेस के आधार पर नियमित संवर्ग में रखा जाएगा। इसके बाद वे अगले 15 साल के पूरे कार्यकाल के लिए काम करेंगे। जबकि अन्य 75% अग्निवीरों को उनके दूसरे करियर में मदद के लिए उनके मासिक योगदान द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित 11-12 लाख रुपये के एक्जिट या ''सेवा निधि'' पैकेज के साथ-साथ कौशल प्रमाण पत्र और बैंक ऋण के साथ भेजा जाएगा।

पक्ष में तर्क

- यह योजना सशस्त्र बलों को काफी युवा बना देगी। भारत में वर्तमान औसत आयु प्रोफाइल 32 वर्ष है। इस योजना को लागू करने से यह घटकर 27-28 साल हो जाएगी।
- यह योजना रक्षा पेंशन बिल को भी कम करेगी, जो कि सरकार की वित्तीय स्थिति पर काफी बोझ है, खासकर वन-रैंक-वन पेंशन योजना के लागू होने के बाद। अनुमानित गणना के मुताबिक इस मॉडल के जरिए सिर्फ एक व्यक्ति से सरकार को लगभग 11.5 करोड़ की बचत होगी। 2022-23 के लिए भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से 1.2 लाख रुपये केवल पेंशन घटक के लिए है।
- यह योजना भविष्य के लिए तैयार सैनिकों के साथ एक आधुनिक सेना तैयार करेगी, जिसे नई तकनीकी में प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो कि इन दिनों युद्ध का एक अनिवार्य हिस्सा है।
- युवा सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में तैनात किया जा सकता है। यह तेजी से प्रतिक्रिया और चपलता के मामले में लाभदायक होगी।
- यह योजना भारत के युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी।
- चार साल के बाद इन युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे क्योंकि उन्हें सशस्त्र बलों में उनके कार्यकाल के दौरान विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। वे अपनी अगली नौकरियों या व्यवसायों के लिए कड़ी मेहनत और कर्तव्यपरायणता के सैन्य लोका. चार को भी ले के जाएंगे।
- यह योजना चार वर्षों के बाद लगभग 11 से 12 लाख की ''सेवा निधि'' भी प्रदान करेगी, जो युवाओं को वित्तीय संकटों से स्वतंत्र कर देगी ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने करियर की राह पर चल सकें।
- चार वर्षों के बाद, अग्निवीर नागरिक समाज में लौट आएंगे, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं और जनसंख्या में देशभक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं।
- यह योजना सरकार को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक पूंजीगत व्यय करने की अनुमति देगी क्योंकि इससे रक्षा बजट के पेंशन घटक में कमी आएगी। वर्तमान समय में, प्रौद्योगिकी संख्यात्मक शक्ति से अधिक विनाशकारी हो सकती है।

इसके खिलाफ तर्क

- कुछ सैन्य हलकों में चिंता है कि एक लड़ाकू सैनिक को 4 साल में प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है, और यह योजना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करती है। 4 साल के भर्ती में प्रशिक्षण, अधिकृत अवकाश और अस्थाई ड्यूटी 90 सप्ताह तक खाएंगे। इस प्रकार कम प्रशिक्षण का विचार उस कौशल को कमजोर बनाता है जिसके लिए सशस्त्र बल अपने कैडर को इतनी लगन से प्रशिक्षित करते हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षण सैनिक के जीवन के लिए भी हानिकारक होगा।
- चार साल बाद सशस्त्र बलों से युवाओं

की छंटनी भी सुरक्षा समस्याएं पैदा करेगी क्योंकि यह बहुत से सैन्य कौशल में प्रशिक्षित होंगे। यदि वे बेरोजगार रहते हैं, तो वे एक अपराध सिंडिकेट, कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों आदि के शिकार हो सकते हैं।

- इनमें से अधिकांश सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी नौकरी या पेंशन और स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा; इस प्रकार सैनिकों और राष्ट्र के बीच निहित सामाजिक अनुबंध कि राष्ट्र अपने सैनिकों की सेवानिवृत्ति या जीवन की हानि के बाद भी उनकी देखभाल करेगा, खतरे में है।
- सेवा में 'ऑल इंडिया ऑल क्लास' की भर्ती एक सैनिक की अपनी रेजिमेंट के प्रति निष्ठा को कम कर सकती है।
- भविष्य में, अधिकांश सेना इन अग्निवीरों से बनी होगी। यह स्थिति इन अग्निवीरो की गैर-निरंतरता के कारण कार्य प्रणाली संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है।
- सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किया गया कौशल मुख्य रूप से युद्ध कौशल से संबंधित है; इस प्रकार, भविष्य की नौकरियों में उनकी उपयोगिता संदिग्ध है।
- यह योजना सभी हितधारकों, विशेषकर सेना में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के बीच व्यापक सार्वजनिक चर्चा के बिना लाई गई। इसके कारण देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय रुझान

दुनिया भर में प्रमुख सशस्त्र बल संख्या घटाने और उन्हें दक्ष बनाने की ओर बढ़ रहे हैं।

- चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार अपनी सेना को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य सेना के आकार को 1 मिलियन से कम करना है, जो वर्तमान में 2.3 मिलियन है। चीन अपनी नौसेना और वायु सेना का आकार भी बढ़ाना चाहता है। वह अपने बलों को और हाईटेक बनाने पर कार्य कर रहा है।
- ब्रिटेन में, पिछले एक दशक में सशस्त्र बलों का आकार लगातार सिकुड़ रहा है। यह राष्ट्रीय साइबर बल, स्वायत्त हथियार प्रणाली और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण निवेश करता है।
- रूस ने भी क्लासिक हार्ड पावर और ट्रूप साइज के सिद्धांत को खारिज कर दिया है। इन दिनों, रूसी सैनिक ब्रिगेड से लड़ते हैं, बड़े डिवीजनों से नहीं।
- अमेरिका भी सैनिकों की संख्या में कटौती कर अपने सैन्य बजट को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। ये कटौती नौसेना और वायु सेना की तुलना में जल सेना में काफी अधिक होगी। अत्याधुनिक तकनीकी में निवेश करके अमेरिका यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि उसके सशस्त्र बलों की विनाशकारी शक्ति से समझौता न हो।

आगे का रास्ता

जबकि सरकार अपनी अग्निपथ योजना के साथ आगे बढ़ रही है, उसे कुछ संबंधित चिंताओं को दूर करना चाहिए। कम समय में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल को नए तरीकों से डिजाइन किया जाना चाहिए। जाति, धर्म और क्षेत्र-आधारित रेजीमेंटों की संस्कृति को एक समान लक्ष्य पर आधारित रेजिमेंटल एकता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अग्निवीरों को दिया गया कौशल प्रमाणन भविष्य की नौकरियों और जिम्मेदारियों में उपयोग का होना चाहिए। सरकार को छँटनी हो रहे युवाओं को अवसर देने के लिए निजी खिलाड़ियों को भी लूप में लाना चाहिए। ये उपाय अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाएंगे और भारतीय सशस्त्र बलों की घातकता को मजबूत करेंगे।

NOTES

भारत पर दो टाइम जोन से प्रभाव

संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व से पश्चिम तक 4,800 किमी तक फैला हुआ है और इसे छह टाइम जोन में विभाजित किया गया है। इसके विपरीत, भारत गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 3,000 किमी से अधिक में फैला हुआ है, लेकिन इसका केवल एक ही टाइम जोन है। जबकि अमेरिका में इस बारे में बहस चल रही है कि क्या उन्हें छह टाइम जोन से दो टाइम जोन में स्विच करना चाहिए, दूसरी ओर, भारत लंबे समय से एक टाइम जोन से दो में जाने के बारे में बात कर रहा है। चीन के पास भी एक टाइम जोन है।

भारतीय मानक समय (IST)

भारतीय मानक समय की गणना 82.5°E देशांतर के आधार पर की जाती है जो उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के पास मिर्जापुर शहर के ठीक पश्चिम में है, जो ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) से साढ़े पांच घंटे आगे है, जिसे अब यूनिवर्सल समन्वित समय (UTC) कहा जाता है और इस मानक टाइम जोन का पूरे भारत में पालन किया जाता है। भले ही देश के पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग.3000 किमी है।

भारत में समय को निर्धारित करने वाली व्यवस्था की देख रेख करने वाला सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), नई दिल्ली है, जो पांच सीजियम परमाणु घड़ियों का उपयोग करके समय रिकॉर्ड करता है।

भारत के पश्चिमी-अधिकांश भाग और पूर्वी-अधिकांश बिंदु के बीच समय का अंतर लगभग दो घंटे है, जिसका प्रभाव यह है कि सूर्य देश के बाकी हिस्सों की तुलना में उत्त. र-पूर्व में बहुत पहले उगता है और डूबता है। भारत में पांच राज्य जिनसे मानक मेरिडियन गुजरता है, वे हैं:

- उत्तर प्रदेश;
- मध्य प्रदेश;
- छत्तीसगढ़;
- ओडिशा; और
- आंध्र प्रदेश।

एकल टाइम जोन: पक्ष और विपक्ष तर्क

- **पक्ष में :**

सिंगल टाइम जोन के समर्थकों का तर्क है कि भारत चीन जितना बड़ा नहीं है, जो कई टाइम जोन (देश पाँच टाइम जोन में फैला हुआ है) को बनाए रखता है। भारत में दो टाइम जोन को लागू करने से न केवल लंबी दूरी की रेलवे समय सारिणी में बल्कि व्यवसाय के संचालन के तरीके में भी परेशानी होगी। , चाहे आप भारत में कहीं भी हों, यह देश को एकजुट करता है। कोई भी जो देश में यात्रा कर रहा है, उसे चिंता करने और समय बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। देश भर में होने वाली सभी घटनाओं को अपरिवर्तित समय में रिपोर्ट किया जाता है।

- **विपक्ष में :**

मुख्य भूमि भारत के एकीकृत समय के साथ बने रहने के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामान्य से अधिक समय तक काम करने और कम सोने की शिकायतें आती है, जो लंबे समय तक उत्पादकता के स्तर को प्रभावित करता है।

पूर्वोत्तर में,

- सूरज सुबह 4 बजे उगता है, और लोगों को काम करने के लिए सुबह 10 बजे तक इंतजार करना पड़ता है - क्योंकि भारत के मानक व्यावसायिक घंटे ऐसे ही निर्धारित किये गये हैं ।
- जब वे शाम 6 बजे तक काम करते हैं, तब तक पूर्वोत्तर में काली रात हो जाती है जिससे उन्हें काफी दिक्कत होती है। उन्हें सामाजिककरण के लिए बहुत कम समय मिल पाता है और इस प्रकार एक खराब स्वास्थ्य कार्य-जीवन संतुलन (Poor Healthy Work Life Balance) होता है जो उत्पादकता को कम कर सकते हैं।

कुछ तथ्य

- भौगोलिक "शून्य रेखा" ग्रीनविच, लंदन से निकलती है।
- यह GMT की पहचान करता है, जिसे अब यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम (UTC) के रूप में जाना जाता है, जिसकी निगरानी फ्रांस के वजन और माप ब्यूरो (BIPM) द्वारा की जाती है।
- ग्रीनविच मीन टाइम की स्थापना रॉयल ऑब्जर्वेटरी द्वारा 1675 में समुद्र में नेविगेटरों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी।

दो टाइम जोन : पक्ष में तर्क

- **प्रभावी योजना:**

भारत लंबे समय से दो टाइम जोन की व्यवहार्यता पर बहस कर रहा है। असम में चाय बागानों ने लंबे समय से अपनी घड़ियों को आईएसटी से एक घंटे आगे रखा है, जि. ससे यह उनका अनौपचारिक टाइम जोन बन गया है। दो टाइम जोन होने के लिए आर्थिक लाभ भी हैं; लोग अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और योजना बनाने में सक्षम होंगे।

- **बिजली की बचत:**

राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार, दो टाइम जोन भारत को एक वर्ष में 2.7 बिलियन यूनिट बिजली बचाने में मदद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के पूर्वी हिस्से में अधिकांश कार्यालय और स्कूल सूर्यास्त से पहले अच्छी तरह से खुले रहते हैं। बिजली की गंभीर कमी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिजली का संरक्षण महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय

ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि लगभग 24 मिलियन भारतीयों के पास बिजली तक पहुंच नहीं है। सीएसआईआर-एनपीएल के अनुसार, भारत प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपये की बचत कर सकता है यदि वह दो टाइम जोन को लागू करके बिजली का संरक्षण कर सकता है।

- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार:**

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टाइम जोन का प्रभाव एक छोटा सा ज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। राष्ट्रों के टाइम जोन पर ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक पैटर्न, और भागीदारों का प्रभाव पड़ता है। अनुसंधान के अनुसार, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने एक से अधिक टाइम जोन में आर्थिक व्यापार से लाभ उठाया है। वे अपनी ताकत और कमियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थे, जिसका सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हुआ।

- **सकारात्मक स्वास्थ्य:**

एक से अधिक टाइम जोन वाले देशों के कार्य और सोने के कार्यक्रम अलग-अलग टाइम जोन में संचालित होते हैं। टाइम जोन बदलने से कर्मचारियों को स्वस्थ खाने, सोने और काम करने की आदतें विकसित करने की अनुमति मिली, जिसके सकारात्मक परिणाम हुए।

- **श्रम को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें:**

मोबाइल फोन के व्यापक प्रचलन को देखते हुए - जो स्वचालित रूप से समय परिवर्तन के लिए समायोजित कर सकते हैं - इस तरह के परिवर्तन की शुरुआत के लिए बाधाएं वर्षों से कम हो गई हैं।

दो टाइम जोन : विपक्ष में तर्क

- **ट्रेन दुर्घटनाओं की संभावना:**

इसकी जटिलता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2002 में इसी तरह के एक विचार को खारिज कर दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना था हर समय जोन सीमा-क्रॉसिंग पर घड़ी को रीसेट करने की आवश्यकता से ट्रेन दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती थी।

- **राजनीतिक मुद्दा:**

चूंकि राजनीतिक प्राधिकरण टाइम जोन को नियंत्रित करता है, इसलिए निवासियों द्वारा अपने देशों के टाइम जोन के बारे में महसूस किए गए अधिकांश फायदे या नुकसान आर्थिक की तुलना में राजनीतिक या सामाजिक अधिक थे।

- **भ्रम:**

दो टाइम जोन बहुत भ्रम पैदा करेंगे और लोगों को शिक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी। ये राज्य के संसाधनों और अर्थव्यवस्था के नुकसान का कारण भी बन सकते है। दो टाइम जोन की सीमा पार करने वाले लोगों को हर बार जब वे सीमा पार करते हैं तो समय बदलना पड़ेगा जिससे भ्रम उत्तपन्न हो सकता है।

- **पूर्वोत्तर के लिए अलगाव की भावना:**

देश के बाकी हिस्सों से अलग टाइम जोन होने से, पूर्वोत्तर राज्य अपने को अलग-थलग महसूस कर सकते हैं।

हाल के प्रयास:

पिछले साल, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनु. संधान परिषद की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल) ने दो टाइम जोन को आईएसटी-I (यूटीसी + 5.30 एच) और आईएसटी-II (यूटीसी + 6.30 एच) को कॉल करने का प्रस्ताव दिया था। सीमां. कन की प्रस्तावित रेखा 89°52'E पर है, जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच की संकीर्ण सीमा है।

- लाइन के पश्चिम में राज्य आईएसटी का पालन करना जारी रखेंगे (जिसे आइ. एसटी-आई कहा जाता है)।
- रेखा के पूर्व के राज्य - असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - आईएसटी-II का पालन करेंगे।

प्रस्तावित विकल्प:

- **डेलाइट सेविंग टाइम**

कई देशों में ''डेलाइट सेविंग टाइम'' (डीएसटी) का व्यवस्था भी है, जिसमें गर्मियों में समय एक घंटे तक एडवांस (या घड़ियों को आगे रखा जाता है) और सर्दियों के दौरान एक घण्टे पीछे कर लिया जाता है। यह लोगों को गर्मियों में लंबे समय तक सूरज की रोशनी का आनंद लेने और सर्दियों के दौरान देर से सूर्योदय और शुरुआती सूर्यास्त की असुविधाओं से बचने में सक्षम बनाता है।

- **आईएसटी को आगे बढ़ाना:**

एक बार आईएसटी को आधे घंटे तक आगे बढ़ाने से, यह स्थायी रूप से जीएमटी से छह घंटे आगे माना जायेगा। आईएसटी को आधे घंटे तक आगे बढ़ाने का यह प्रस्ताव अन्य दो प्रस्तावों (टाइम जोन और डीएसटी के) में पकड़ी गई समस्याओं से बचाता है, लेकिन यह शाम के घंटों के दौरान अधिकतम ऊर्जा बचत प्रदान करेगा जब निरंतर बिजली की आपूर्ति करने में विफलता रहती हैं।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता के बाद एक एकल टाइम जोन को अपनाने का भारत का निर्णय एक बुद्धिमत्ता थी। उस समय हमारी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निरक्षर था और दो टाइम जोन बहुत सारी जटिलताओं को जन्म देता। लेकिन साक्षरता दरों में सुधार करने में किए गए प्रभावशाली कदमों के साथ, यह अब व्यावहारिक मामला नहीं है।

पूर्वोत्तर राज्य दो टाइम जोन के बारे में मुखर रहे हैं और यदि विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो यह निस्संदेह लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

भारत एकल टाइम जोन का उपयोग करता है क्योंकि यह अपने रणनीतिक और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है, लेकिन आर्थिक जरूरतों को देखते हुए यह बदलने का समय है।

भारत अवसरों का लाभ उठाकर और टाइम जोन के मतभेदों का निदान करके आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

एफडीआई अनुमोदन को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता

संदर्भ:

प्रेस नोट 3, जिसका उद्देश्य विदेशी संस्थाओं द्वारा अवसरवादी अधिग्रहण को रोकना है, की वर्तमान आर्थिक स्थिति में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

जैसा कि दुनिया भर की कंपनियों ने 2020 में महामारी की अनिश्चितता से जूझना शुरू कर दिया, कई अर्थव्यवस्थाओं ने अपने देश में महामारी से तनावग्रस्त संस्थाओं के अवस. रवादी अधिग्रहण के बारे में चिंताएं उठाना शुरू कर दिया है ।

इन देशों ने विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवे. दनशील क्षेत्रों में परिसंपत्तियां विदेशी हाथों में न हों जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हैं।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, भारत ने 2020 में प्रेस नोट 3 (पीएन 3) पेश किया, जिसके लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश में स्थित एक इकाई से सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों को सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत लाया गया था।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या है?

किसी विदेशी देश में स्थित किसी व्यक्ति या फर्म से किसी देश में किया गया को. ई भी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहलाता है।

एफडीआई के साथ, विदेशी कंपनियां दूसरे देश में दिन-प्रतिदिन के संचालन के साथ सीधे शामिल होती हैं।

इसका मतलब है कि वे न केवल उनके साथ पैसा ला रहे हैं, बल्कि ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी भी ला रहे हैं।

आम तौर पर, एफडीआई तब होता है जब कोई निवेशक विदेशी व्यापार संचालन स्थापित करता है या विदेशी व्यावसायिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करता है, जिसमें विदेशी कंपनी में स्वामित्व स्थापित करना या ब्याज को नियंत्रित करना शामिल है।

यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है जहां विदेशी इकाई केवल एक कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदती है।

एफडीआई आमतौर पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था में होता है जिसमें विकास की संभावना होती है और एक कुशल कार्यबल भी होता है।

एफडीआई आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है और भारत के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसीलिए, एक मजबूत और आसानी से सुलभ एफडीआई व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

प्रेस नोट 3 (PN3) 2020 के बारे में

प्रेस नोट 3 (2020 श्रृंखला) को अप्रैल 2020 में महामारी के शुरुआती दिनों के दौरान लाया गया था - इसे महामारी के दौ. रान अवसरवादी अधिग्रहणों के प्रति भारतीय कंपनियों की कमजोर होने की चिंताओं के तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में लाया गया था।

प्रेस-नोट 3 के कार्यान्वयन के लिए चुनौ. तीपूर्ण हिस्सा यह था कि यह लाभार्थी स्वामी की पहचान के लिए सीमा को परिभाषित नहीं करता था।

प्रेस नोट एफडीआई नीति को, दो मौलिक सन्दर्भ में परिवर्तित करता है:

- सबसे पहले, यह उन देशों की सूची का विस्तार करता है जिनके निवेशक अब स्वच. ालित मार्ग के तहत भारत में निवेश करने के योग्य नहीं हैं।
- दूसरा, भारत में एक निवेश - जो अन्यथा स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आता है - अब सरकारी मार्ग के अंतर्गत आता है यदि यह किसी ऐसी संस्था से है जिसका ''लाभदायक स्वामी'' ऐसे सीमावर्ती देश से है। इन परिवर्तनों का समग्र एफडीआई व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालता है

प्रेस नोट 3 (PN3) के वर्तमान मुद्दे:

हालांकि, पीएन 3 जारी करने के बाद से महत्वपूर्ण विकास की एक श्रृंखला रही है, जिसके परिणामस्वरूप इसे अपडेट करने और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता होती है। इस अवधि के दौरान, सरकार ने कई साहसिक सुधार उपायों को भी पेश किया जैसे

- यात्रा और पर्यटन को खोलना
- भारतीय परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 2012 में लगाए गए विवादास्पद पूर्वव्यापी कर को समाप्त करना
- केयर्न (Cairn) और वोडाफोन सहित 17 कंपनियों के साथ परेशान करने वाले मुकदमों को समाप्त करना
- पहले के बुरे हालत में चल रहे दूरसंचार क्षेत्र में एक नई जान फूंकना।

वर्तमान स्वस्थ रुझान संभावित रूप से 'अवसरवादी अधिग्रहण' के किसी भी प्रयास को दूर कर सकते हैं जैसा कि पहले डर था। वैश्विक मोर्चे पर, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भू-राजनीतिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और संभावित रूप से भारी मुद्रास्फीति के दबाव पैदा किए हैं, जिससे देशों को अपनी नीतियों की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

इस स्थिति में, वैध निवेश को बढ़ावा देने

के लिए पीएन 3 की समीक्षा करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से 'पूल किए गए फंड' जैसे स्रोतों से।

ये निवेश उपकरण हैं जो कई निवेशकों से पैसे एकत्रित करते हैं और फंड प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं जो स्वतंत्र रूप से और पेशेवर रूप से अपने निवेशकों के लिए रिटर्न देने के लिए निवेश रणनीति चलाते हैं।

सुधार की जरूरत :

पीएन 3 को सरल बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त क्षेत्र हैं जिन पर भी विचार किया जा सकता है:

- **सुविधाजनक क्षेत्रो में छूट:**

प्रभावी रूप से, गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में, निवेश मार्ग की परवाह किए बिना, एक भारतीय कंपनी के आर्थिक हितों के 10 प्रतिशत (या यहां तक कि 5 प्रतिशत) से कम का गठन करने वाली प्रतिबंधित संस्थाओं के निवेश को पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है।

इसका कारण यह होगा कि 'प्रतिबंधित संस्थाओं' की ऐसी अल्पसंख्यक शेयरधारिता संस्थाओं के नियंत्रण/दिशा को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

- **'लाभकारी स्वामित्व' के दायरे और दायरे पर स्पष्टीकरण:**

चूंकि पीएन 3 के तहत लाभकारी स्वामित्व के दायरे और सीमा का विस्तार नहीं किया गया है, इसलिए 'लाभकारी स्वामित्व' की स्वीकार्य सीमा पर काफी चर्चा हुई है।

- **कई अन्य विनियमों से संकेत**

निवेशकों के लिए छूट से जुड़ा एक तंत्र हो सकता है जहां अंतिम लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण 25 प्रतिशत से कम है।

इसमें विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं, जिनमें प्रतिबंधित शेयरधारकों के पास सूचीबद्ध स्टॉक का 25 प्रतिशत से कम हिस्सा है।

- **भारतीय कंपनियों में आगे निवेश जहां प्रतिबंधित संस्थाएं मौजूदा शेयरधारक हैं:**

यह सर्वविदित है कि भारत में कई स्टार्ट-अप क्षेत्रों (ई-कॉमर्स, प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया, आदि) में पर्याप्त मात्रा में चीनी निवेश है। पीएन 3 के तहत नए निवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, आने वाले और मौजूदा निवेशक इस तरह के स्टार्ट-अप द्वारा फंड जुटाने के दौर में भाग लेने की तलाश में संकोच कर सकते हैं।

- जैसा कि पीएन 3 के पीछे का इरादा अवसरवादी अधिग्रहणों को रोकने के लिए किया गया है, पहले से ही स्वामित्व वाली ऐसी प्रतिबंधित संस्थाओं द्वारा नियंत्रित कंपनियों में, प्रतिबंधित संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण या अधिग्रहण के भविष्य के दौर की स्क्रीनिंग को शिथिल किया जा सकता है क्योंकि अवसरवादी अधिग्रहण का सवाल नहीं उठता है।
- अनुमोदन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और समीचीनता की आवश्यकता है। पीएन 3 के संदर्भ में एक और चुनौती प्रस्तावों की सुरक्षा मंजूरी के लिए लिया गया समय है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, 2020 से पीएन 3 के तहत लगभग 347 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से केवल 66 को अब तक मंजूरी दी गई है।

कुछ तथ्य

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह को आकर्षित किया, जो ऑन-ईयर 1.95 प्रतिशत अधिक है।
- भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम कुल एफडीआई प्रवाह को आकर्षित किया है और यह पिछले वित्त वर्ष 2019-20 (यूएस $74.39 बिलियन) की तुलना में 10% अधिक है।
- सिंगापुर अकेले इक्विटी प्रवाह के 27 प्रतिशत के साथ शीर्ष निवेश करने वाला देश है।
- इसके बाद अमेरिका 21 प्रतिशत पर प्रवाह के साथ दूसरे एवं मॉरीशस का स्थान तीसरा है जो वित्त वर्ष 22 में 16 प्रतिशत प्रवाह पर भारत के लिए एफडीआई के शीर्ष स्रोतों में से एक बना हुआ है।
- कर्नाटक पुनः शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है, जिसमें कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 38 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद महाराष्ट्र में 26 प्रतिशत और दिल्ली में 14 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
- कर्नाटक के अधिकांश इक्विटी प्रवाह की सूचना इन क्षेत्रों - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में दी गई है, जिसमें कुल एफडी. आई इक्विटी प्रवाह का 35 प्रतिशत हिस्सा है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए वित्त वर्ष 22 के दौरान 20 प्रतिशत जबकि शिक्षा के मामले में 12 प्रतिशत था।
- विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 2020-21 (12.09 अरब डॉलर) की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 (21.34 अरब डॉलर) में 76 प्रतिशत बढ़ गया है।

आगे की राह :

जब चीनी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न सुरक्षा जोखिम बना रहता है, भारतीय संस्थाओं को धन जुटाने की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति और रणनीतिक क्षेत्रों में।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड महामारी के दौरान और बाद में बहुत अधिक लचीलापन और वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जैसा कि एफडीआई प्रवाह के लगातार बढते रहने और यूनिकॉर्न की रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि से प्रमाणित है, जो इस अवधि के दौरान 100 के आकड़ें को पार कर गया है। अब जब अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है, तो अधिक सुविधा, पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णय लेने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

राष्ट्रीय

1 अंतर्राज्यीय परिषद

खबरों में क्यों:

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि ''सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने'' के लिए हर साल अंतर्राज्यीय परिषद की कम से कम तीन बैठकें होनी चाहिए।

अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में

यह एक निकाय है जिसे ''भारत में केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य समन्वय और सहयोग के लिए'' गठित किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी, जिसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति ऐसी संस्था का गठन कर सकते हैं।

सरकारिया आयोग: 1988 में, सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में मौजूद होना चाहिए, और 1990 में यह एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आया।

1990 में अपने गठन के बाद से, निकाय केवल 11 बार मिली हैं, हालांकि इसकी प्रक्रिया में कहा गया है कि इसे हर साल कम से कम तीन बार मिलना चाहिए।

संरचना:

परिषद की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

- प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
- सदस्यों में विधानसभाओं के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
- अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।
- केंद्र की मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित, इसके सदस्य भी हैं।

कार्य:

- परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना है।
- उन विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें दो राज्यों या राज्यों और केंद्र के समान हित हों।
- नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना।
- परिषद मूल रूप से विभिन्न सरकारों के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए है।

चुनौतियां:

- अनुशंसा निकाय: संघ और राज्यों या राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करने के लिए यह सिर्फ एक सिफारिशी निकाय है।
- नियमित बैठकों का अभाव: नियमित बैठकों का अभाव है, परिषद की पिछले छह वर्षों में केवल एक बार बैठक हुई है - और जुलाई 2016 से कोई बैठक नहीं हुई है।
- तकनीकी और प्रबंधन विशेषज्ञों की कमी: इसमें प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक स्वायत्तता के साथ-साथ तकनीकी और प्रबंधन विशेषज्ञों की कमी है।

अंतरराज्यीय परिषद की अंतिम बैठक के बारे में

2016 की बैठक में 2010 में प्रकाशित केंद्र- राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार शामिल था। बैठक में सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्यों ने बढ़ते ''केंद्रीकरण'' के बीच संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए मत व्यक्त किया। संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करना, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है, पर चिंता व्यक्त की। आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और सिंक्रनाइजेशन पर ध्यान देने के साथ आंतरिक सुरक्षा और पुलिस सुधार और पुलिस आधुनिकीकरण पर भी चर्चा की गई। बिहार के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

आगे का रास्ता:

अनुच्छेद 263 में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए ताकि परिषद को केवल एक सलाहकार निकाय होने के बजाय अधिक शक्ति और अधिकार दिया जा सके। अंतर्राज्यीय परिषद एक स्थायी निकाय बनाया जाना चाहिए जो सरकारिया आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक था।

2 भारत गौरव योजना

हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने नई दिल्ली से 18 दिवसीय श्री रामायण यात्रा शुरू की। रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी- I के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आईआरसीटीसी ने अपनी पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का उद्घाटन किया है। यह ट्रेन भारत और नेपाल के बीच लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह ट्रेन स्वदेश दर्शन के तहत रामायण सर्किट पर चलेगी और उन स्थानों पर जाएगी जहां भगवान राम, देवी सीता और

भगवान लक्ष्मण ने अपने वनवास के 14 वर्षों को बिताया था।

भारत गौरव ट्रेनों के बारे में

- नवंबर 2021 में भारतीय रेलवे ने निजी कंपनियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को भारत के लोगों और विदेशियों को प्रदर्शित करने के लिए थीम-आधारित भारत गौरव ट्रेनें चलाने की अनुमति दी।
- यह योजना थीम-आधारित ट्रेनों को चलाने के लिए पर्यटन क्षेत्र में पेशेवरों की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य भारत की विशाल पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए थीम आधारित रेलगाड़ियों को चलाने के लिए पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों की क्षमता का लाभ उठाना भी है।
- यह भारत गौरव योजना पेशेवर तथा अनुभवी टूर ऑपरेटरों को जोड़ने में मदद करेगी और देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
- वर्तमान में, आईआरसीटीसी पहले से ही कई पर्यटक सर्किट ट्रेनें चला रहा है। इस नीति के लागू होने से सभी पर्यटक सर्किट ट्रेनों का संचालन इस नीति के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

योजना का महत्व

- **निजी कंपनियां चलाएंगी विशेष ट्रेन:** यह पर्यटन क्षेत्र में डोमेन ज्ञान रखने वाले निजी खिलाड़ियों को इन विशेष ट्रेनों को चलाने की अनुमति देता है।
- **इंक्रीमेंटल रेवेन्यू:** रेलवे को कारोबार के एक नए स्ट्रीम से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिलेगा।
- **निजीकरण :** इससे कार्गो और यात्री ट्रेनों के संचालन में और अधिक निजीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

एक पर्यटक सर्किट के बारे में

- टूरिस्ट सर्किट को एक ऐसे मार्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कम से कम तीन प्रमुख पर्यटन स्थल जो एक ही गांव या शहर में नहीं हैं और जिनके बीच की दूरी भी अधिक नहीं हो ।
- पर्यटक सर्किट में निश्चित प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए। प्रवेश करने वाले पर्यटक को सर्किट के मुख्य स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित होना चाहिए।
- थीम-आधारित टूरिस्ट सर्किट धर्म, संस्कृति, जातीयता आदि जैसे विशिष्ट विषयों के आसपास के सर्किट होते हैं। एक थीम-आधारित सर्किट को एक राज्य तक सीमित किया जा सकता है या एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाला एक क्षेत्रीय सर्किट भी हो सकता है।

अन्य योजनाएं

- **स्वदेश दर्शन योजना:**

स्वदेश दर्शन केंद्र सरकार की योजना है, जिसे 2014-15 में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था।

- **प्रसाद योजना:**

पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन' (प्रसाद) शुरू किया गया था।

- **बौद्ध सम्मेलन:**

बौद्ध सम्मेलन भारत को बौद्ध गंतव्य और दुनिया भर के प्रमुख बाजारों के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वैकल्पिक वर्ष में आयोजित किया जाता है।

- **देखो अपना देश पहल:**

यह नागरिकों को देश के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने और भारत के संस्कृतिक पहलुओं को देखने और समझने के लिए एक पहल है जिससे देश में पर्यटन स्थलों में घरेलू पर्यटन पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम बनाया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय

1 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

चर्चा मे क्यों?

21 जून 2022 को पूरे विश्व मे 8वां योग दिवस मनाया गया।

पृष्ठभूमि-

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नें 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी।

भारत मे योग की उत्पत्ति कब और कैसे हुई?

भगवान शिव को योग का प्रवर्तक माना जाता है, उन्हें आदियोगी कहा जाता है अर्थात् पहला योगी। जबकि जनसामान्य के बीच योग को लाने का श्रेय सप्तर्षियों का है। वेद,

बताते हैं कि कैसे एक आदियोगी के रूप में शिव की दूसरी शिक्षा सप्तर्षियों को समर्पित थी। ऐसा कहा जाता है कि शिव वर्षों से ध्यान में बैठे थे, बहुत से लोग उत्सुकता से उनके पास आते थे, लेकिन अधिकतर वहां से चले गए क्योंकि उन्होंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनमे से सात लोग रुके रहे, वे शिव से सीखने के लिए इतने दृढ़ थे, कि वे 84 वर्षों तक स्थिर बैठे रहे। इसके बाद ग्रीष्म संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तर से दक्षिणी भाग में जा रहा था, तब शिव ने इन 7 प्राणियों पर ध्यान दिया – वे अब उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। अगली पूर्णिमा, 28 दिन बाद, शिव आदिगुरु (प्रथम गुरु) में बदल गए, और योग के विज्ञान को सप्तर्षियों तक पहुँचाया।

योग की परम्परा को महर्षि पतंजलि ने आगे बढाया। उनके अनुसार मन को इधर-उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। इनके अनुसार योग के 3 प्रकार हैं- आसन, प्राणायाम और ध्यान। वर्तमान मे बाबारामदेव, श्री श्री रविशंकर इत्यादि योग गुरुओ के प्रयास से भारतीय योग को अन्तराष्ट्रीय पहचान मिली है।

21 जून को योग दिवस मानाने के कारण

21 जून ग्रीष्म संक्रांति का दिन है। जून संक्रांति के दौरान, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है या हम कह सकते हैं कि जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करता है। योग की दृष्टि से यह समय संक्रमण काल यानि ध्यान के लिए बेहतर समय है। उत्तरी गोलार्ध में यह तिथि वर्ष का सबसे लंबा दिन भी है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है।

योग दिवस 2022 की थीम-

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक थीम रखी गयी थी । 2022 की थीम है 'मानवता के लिए योग'।

योग के लाभ

- योग मस्तिष्क में तंत्रिका पैटर्न को बहुत प्रभावित कर सकता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हो सकता है।
- योग शक्ति, संतुलन और लचीलेपन में सुधार करता है।
- योग पीठ दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है।
- योग गठिया के लक्षणों को कम कर सकता है।
- योग से दिल की सेहत को फायदा होता है।
- योग आपको आराम देता है, जिससे आपको बेहतर नींद लेने में मदद मिलती है।
- योग का मतलब अधिक ऊर्जावित होना और मन को तरोताजा करना हो सकता है।
- योग आपको तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है।
- योग आपको एक सहयोगी समुदाय से जोड़ता है।
- योग बेहतर आत्म-देखभाल को बढ़ावा देता है।

2 हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

चर्चा में क्यों ?

जुलाई 2021 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया भर में "हेट स्पीच के प्रसार और प्रचार" पर वैश्विक चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए "हेट स्पीच का मुकाबला करने में अंतर-धार्मिक और अंतर-सांस्कृतिक संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देने" पर एक प्रस्ताव अपनाया था। इसी प्रस्ताव के अन्तर्गत 18 जून को हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस साल 18 जून को प्रथम दिवस मनाया गया है।

हेट स्पीच से सम्बंधित अन्य मुद्दे - पृष्ठभूमि

हेट स्पीच का मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक पहल है जो 18 जून 2019 को शुरू की गई हेट स्पीच पर संयुक्त राष्ट्र की रणनीति और कार्य योजना पर आधारित है।

थीम

हेट स्पीच का मुकाबला करने का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस "नफरत भाषण और अग्रिम समावेश, गैर-भेदभाव और शांति के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए शिक्षा की भूमिका" विषय के तहत मनाया गया।

हेट स्पीच की परिभाषा

संयुक्त राष्ट्र की रणनीति और अभद्र भाषा पर कार्य योजना हेट स्पीच को निम्न प्रकार से परिभाषित करती है-:

"भाषण, लेखन या व्यवहार में किसी भी प्रकार का संचार, जो किसी व्यक्ति या समूह के संदर्भ में अपमानजनक या भेदभावपूर्ण भाषा में, उनके धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग, वंश, लिंग या अन्य पहचान कारक के आधार पर हमला करता है या उपयोग करता है"

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) में "हेट स्पीच" (Hate Speech) की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।

महत्व

यह दिन हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेट स्पीच न केवल भारत के सम्वैधानिक मूल्यों और आदर्शों का खंडन है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को भी कमजोर करती है, जैसे मानव गरिमा, समानता, शांति और सम्मान।

यह हिंसा और असामंजस्य को जन्म देता है

और प्रभावित लोगों या समुदायों को शारी. रिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचाता है। सोशल मीडिया और संचार के अन्य माध्यमों ने भी नफरत भरे भाषणों के विनाशकारी प्रभाव को बढ़ाया है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो इससे व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और संघर्ष बढ़ सकते हैं।

हेट स्पीच के विरुद्ध उपाय

1. न्याय के ढांचे के भीतर जमीनी स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हर स्तर पर सद्भाव और एकजुटता का निर्माण करें।
2. मौलिक मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयास करें ।
3. विश्व भर में समन्वित बहुलवादी संस्कृ. तियों, परंपराओं और सबाल्टर्न इतिहास के बारे में खुद को शिक्षित करें।
4. विश्व भर के समुदायों के भीतर और उनके बीच बिरादरी को मजबूत करने के लिए परंपराओं का निर्माण करें।
5. सांप्रदायिक, जातिवादी, स्त्री के प्रति घृणा और भेदभाव के शिकार लोगों के लिए न्याय की मांग करें।

आगे की राह

आज जब सम्पूर्ण विश्व आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टर धर्मवाद, क्षेत्रवाद सहित अनेकों अलगाववादी कट्टरपंथी विच. ारधाराओ का सामना कर रहा है, इन अनैतिक और विनाशकारी विचारधाराओं के मूल में, ''हेट स्पीच'' का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए विश्व-शांति और सद्भाव को बनाये रखने हेतु ''हेट स्पीच'' को नियंत्रित करने के लिए हम सब को मिलकर संकल्प लेना चाहिए है।

पर्यावरण

1 मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटने करने के लिए विश्व दिवस

खबरों में क्यों?

हाल ही में मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस 17 जून को मनाया गया। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह दिन ऐसा महसूस करने का अवसर प्रदान करता है कि भूमि क्षरण तटस्थता और समस्या-समाधान, मजबूत सामुदायिक भागीदारी तथा हर स्तर पर सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। इस वर्ष की थीम ''एक साथ सूखे से ऊपर उठना या निजात पाना'' है।

मरुस्थलीकरण और सूखा के बारे में

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ''मरुस्थलीकरण जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण है।'' जबकि सूखा उस समय की अवधि है जब किसी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होती है। अपर्याप्त वर्षा तथा बर्फबारी या भूजल को कम करने का कारण बन सकती है। यह न केवल कृषि गतिविधियों को प्रभावित करता है बल्कि पानी की उपलब्धता से संबंधित समस्याओं को भी बढ़ाता है।

इतिहास और महत्व

इस दिन का इतिहास दिसंबर, 1994 में शुरू हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मरुस्थली. करण और सूखे से निपटने का संकल्प लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों और गैर सरकारी संगठनों के समर्थन से इस दिन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इस दिन को शुरू करने का उद्देश्य निम्नीकृत भूमि को स्वस्थ और उपजाऊ भूमि में बदलना है।
यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है विशेष. कर तब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का अनुमान है कि लगभग 180 करोड़ लोग 2025 तक पूर्ण पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में रह रहे होंगे जबकि 2045 तक, मरुस्थलीकरण से लगभग 13.5 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है। पानी, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कच्चे माल, राजमार्ग और घरों जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों की बढ़ती और कभी न खत्म होने वाली मांग के परिण ामस्वरूप पृथ्वी की तीन-चौथाई बर्फ मुक्त भूमि पिघल गई है।

उद्देश्य

इसके मूल रूप से 3 उद्देश्य हैं;
1. मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना।
2. लोगों को बताएं कि मरुस्थलीकरण और सूखे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है अर्थात इसका समाधान भी संभव है और इस उद्देश्य के लिए प्रमुख उपकरणों का प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और सहयोग को मजबूत करना है।
3. गंभीर सूखे और मरुस्थलीकरण का सामना कर रहे देशों में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन को मजबूत करना, मुख्य रूप

से अफ्रीका महाद्वीप में।

भारत और यूएनसीसीडी

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आईयूसीएन के साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक राज्यों में 3.5 वर्षों के पायलट चरण द्वारा भारत में वन परिदृश्य बहाली और बॉन चौलेन्ज पर क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख परियोजना शुरू की है।

2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में, भारत वर्ष 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर खराब और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने के लिए स्वैच्छिक रूप से बॉन चौलेंज प्रतिज्ञा में शामिल हुआ था। भारत द्वारा की गई प्रतिज्ञा, एशिया में सबसे बड़ी प्रतिज्ञाओं में से एक है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, भारत में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% वन (21.71%) और वृक्ष (2.91%) आवरण है।

निष्कर्ष

हाल ही में प्रकाशित पर्यावरण प्रदर्शन सूच. कांक कहता है कि भारत ने पर्यावरण के मुद्दों पर संतोषजनक काम नहीं किया है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसा करके ही हम 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

2 भारतीय जलक्षेत्र से मिले चार नए कोरल

वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से कोरल की चार नई प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पानी से एजोक्सैन्थेलेट कोरल की ये नई प्रजातियाँ पाई गई है।

एजोक्सैन्थेलेट कोरल के बारे में

एजोक्सैन्थेलेट कोरल, कोरल का एक समूह है जिसमें ज़ूजैंथिली नहीं होता है यह सूर्य से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के प्लवकों को पकड़ के पोषण प्राप्त करता है।

वे गहरे समुद्र में पाये जाते हैं, जिनमें से अधि कांश प्रजातियां 200 मीटर से 1,000 मीटर के बीच गहराई में पायी गई हैं। उन्हें जो. क्सांथेलेट कोरल के विपरीत उथले पानी में भी पाया जाता है। नई प्रजातियों का विवरण थालासास: एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मरीन साइंसेज में प्रकाशित किया गया है।

कोरल के सभी चार समूह एक ही परिवार, फ्लैबेलिडे से हैं। ट्रुनकाटोफ्लैबेलम क्रैसम (मिल्ने एडवर्ड्स और हैम, 1848), टी. इन्क्रुस्ताटम (केर्न्स, 1989), टी. एक्युलेटम, (मिल्ने एडवर्ड्स और हैम, 1848), और और टी.इर्रेगुलर (सेम्पेर , 1872) फ्लैबेलिडे परिवार के तहत पहले जापान , फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियाई जल, में पाए गए थे। केवल टी क्रैसम को इंडो-वेस्ट पैसिफिक वितरण की सीमा के साथ पाया गया था।

प्रवाल भित्तियों का महत्व

तटीय सुरक्षा

स्वस्थ प्रवाल भित्तियाँ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं। तटीय क्षेत्रों और समुद्र तटों को मजबूत समुद्री लहरों से बचाती हैं। प्रवाल भित्तियों के बिना कई समुद्र तट और इमारतें, लहर और तूफान के नुकसान की चपेट में आ जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार आने वाले तूफानों से, ये तटीय सुरक्षा सेवाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दिसंबर 2004 की सुनामी में, कुछ तटरेखाओं को स्वस्थ भित्तियों के कारण ही गंभीर क्षति से बचाया गया था।

दवा

प्रवाल भित्तियों को समुद्र की औषधि भंडार कहा जाता है। भित्तियों पर पाए जाने वाले कुछ जीव ऐसे यौगिक उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग मानव अनुप्रयोगों के लिए किया गया है। रीफ पौधों और जानवरों के रसायनों से हृदय रोगों, अल्सर, ल्यूकेमिया आदि जैसे कई रोगों के लिए उपचार में प्रयोग किये जाते हैं। कोरल की अनूठी कंकाल संरचना का उपयोग हड्डी-ग्राफ्टिंग सामग्री बनाने के लिए किया जाता है।

भोजन

रीफ मछलियाँ एक अरब लोगों के लिए खासकर चट्टानों के पास रहने वालों के लिए प्रोटीन का एक स्रोत है। कुछ वाणिज्यिक मछली पकड़ने के उद्यम प्रवाल भित्तियों और आसपास की मछली प्रजातियों पर भी निर्भर करते हैं।

पर्यटन

स्वस्थ चट्टानें स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करती हैं। पर्यटन उद्योग और मत्स्य पालन, प्रवाल भित्तियाँ अरबों डॉलर उत्पन्न करती हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। प्रवाल भित्ति उद्योग वाले देशों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अधिकांश भाग इन्हीं से प्राप्त होता है। एक अध्ययन ने अनुमान लगाया कि प्रवाल भित्तियों का मूल्य $10 बिलियन और प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ $360 मिलियन प्रति वर्ष है।

अंतरिक्ष-विज्ञान

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान के एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर हिंद महासागर में पाए जाने वाले मूंगों में कुछ सौ साल पहले तक भारतीय मानसून की शुरुआत और वापसी में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता थी।

विज्ञान एवं तकनीक

1 महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और UPI की प्रबंध इकाई NPCI के आईटी संसाधनों को 'महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे' के रूप में घोषित किया है।

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्या है?

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत ,क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (CII) को ऐसे ''कंप्यूटर संसाधन'' के रूप में परिभाषित किया जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ को प्रभावित कर सकता है।

सरकार के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी डेटा, डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में घोषित कर सकती है ,ताकि उस डिजिटल संपति की सुरक्षा की जा सके। कोई भी व्यक्ति जो इन सुरक्षित प्रणालियो तक पहुंच प्राप्त करता है या पहुचने का प्रयास करता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है।

CII वर्गीकरण और सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

दुनिया भर की सरकारों ने अपने महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। आईटी संसाधन देश के बुनियादी ढांचे में अनगिनत महत्वपूर्ण संचालन की रीढ़ हैं और CII में उनके परस्पर जुड़ाव के कारण सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाल सकता है जैसे कि पावर ग्रिड में सूचना प्रौद्योगिकी की विफलता से स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अक्तूबर, 2020 में जब भारत महामारी से जूझ रहा था, मुंबई की बिजली ग्रिड की आपूर्ति अचानक बंद हो गई, जिससे बड़े शहर के अस्पतालों, ट्रेनों और व्यवसायों पर विपरीत असर पड़ा। बाद में, एक अमेरिकी फर्म द्वारा किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया कि यह बिजली कटौती एक साइबर हमला हो सकता है, जो कथित तौर पर चीन से जुड़े समूह ने भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर हमले के उद्देश्य से किया गया था। हालाँकि, सरकार ने मुंबई में किसी भी साइबर हमले से इनकार किया।

भारत में CII कैसे सुरक्षित हैं?

जनवरी 2014 में बनाया गया, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने के लिए नोडल एजेंसी है।

NCIIPC, CII के लिए राष्ट्रीय स्तर के खतरों की निगरानी और पूर्वानुमान करेगा। साथ ही नीति मार्गदर्शन, विशेषज्ञता साझा करने और स्थितिजन्य जागरूकता के लिए प्रारंभिक चेतावनी या अलर्ट जारी करेगा। लेकिन, CII प्रणाली की सुरक्षा की मूल जिम्मेदारी उस को चलाने वाली एजेंसी की होगी।

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के लिए किसी भी खतरे की स्थिति में, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, सूचना मांग सकता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों या महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले या सेवा देने वाले व्यक्तियों को निर्देश दे सकता है।

आगे का रास्ता-

CII की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश, इसकी सुरक्षा के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, इन बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देशों को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ साइबर सुरक्षा पेशेवरों की भी आवश्यकता है ताकि वे इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करने के लिए एनसीआईआ. ईपीसी के साथ साझेदारी कर सके।

अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, भारत को अपनी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को अंतरराष्ट्रीय साइबर कानूनों के हिसाब से निर्मित करना चाहिये।

सीआईआई की सुरक्षा के लिए निजी और सार्वजनिक सेक्टर के बीच तालमेल भी महत्वपूर्ण है।

NOTES

2 डीएसटी ने जियोस्पेसियल सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया

खबरों में क्यों?

हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में भू-स्थानिक उद्योग को उदार बनाने के लिए एक जियोस्पेसियल सेल्फ सर्टिफिकेशन (भू-स्थानिक स्व प्रमाणन) पोर्टल लॉन्च किया है।

पोर्टल का उद्देश्य-

यह पोर्टल भारत में भू-स्थानिक उद्योग में उदारीकरण और आत्म प्रमाणन की दिशा में एक बड़ा कदम है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने व्यक्तियों, कंपनियों, संगठनों और सरकारी एजेंसियों द्वारा भू-स्थानिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्व प्रमाणन पोर्टल लॉन्च किया। .

भारत सरकार, प्रधान मंत्री के तत्वावधान में, डेटा और प्रौद्योगिकी-संचालित विक. इस पर ध्यान देने के साथ, देश में व्यापार करने में आसानी और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। 15 फरवरी 2021 को डीएसटी द्वारा नए भू-स्थानिक डेटा दिशानिर्देश जारी करना, भू-स्थानिक उद्योग को उदार बनाने के लिए बहुत आवश्यक परिवर्तन पेश किए।

पोर्टल के बारे में-

- यह पोर्टल मानचित्र से संबंधित गति. विधियों में लगी संस्थाओं को जल्दी और आसानी से खुद को प्रमाणित करने की सु. विधा प्रदान करता है।
- यह व्यक्तियों, कंपनियों, संगठनों और सरकारी एजेंसियों द्वारा भू-स्थानिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने के लिए शुरू किया गया है।
- पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- पोर्टल में संस्थाओं के लिए स्व-प्रमाणन सुविधा नि:शुल्क और सार्वभौमिक है।

भू-स्थानिक पोर्टल द्वारा सुधार-

दिशानिर्देशों द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रों के संग्रह, निर्माण, तैयारी, प्रसार, भंडारण, प्रकाशन, अद्यतन और/या डिजिटलीकरण के लिए पूर्व अनुमोदन, सुरक्षा मंजूरी, लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों की प्रक्रिया का प्रतिस्थापन था। ये सुधार व्यक्तियों, कंपनियों, संगठनों और सरकारी एजेंसियों द्वारा भू-स्थानिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था के साथ भारत राज्य सीमा के भीतर लागू होंगे ।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी क्या है?

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी एक शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी और मानव समाजों के भौगोलिक मानचित्रण और विश्लेषण में योगदान करने वाले आधुनिक उपकरणों की श्रेणी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 'भू-स्थानिक' शब्द उन प्रौद्योगिकियों के संग्रह को संदर्भित करता है जो भौगोलिक जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने, स्टोर करने, प्रबंधित करने, वितरित करने, एकीकृत करने और प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं:

- रिमोट सेंसिंग
- जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली)
- GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम)
- सर्वेक्षण
- 3डी मॉडलिंग

यह बेहतर माप, प्रबंधन और परिसंपत्तियों के रखरखाव, संसाधनों की निगरानी और यहां तक कि पूर्वानुमान और नियोजित हस्तक्षेप के लिए फोरकास्टिंग और निर्देशात्मक विश्लेषण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष

देश में भू-स्थानिक क्षेत्र निवेश के लिए सही स्थिति में है। नवीनतम भू-स्थानिक स्व प्रमाणन पोर्टल प्रौद्योगिकी संचालित विकास के माध्यम से भारत में व्यापार करने में आसानी और उद्यमिता की दिशा में एक सही कदम है।

NOTES

आर्थिक

1 आरबीआई पेमेंट विजन 2025

चर्चा मे क्यों?

हाल मे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपना 'पेमेंट विजन 2025' दस्तावेज जारी किया, जिसका लक्ष्य भारत के डिजिटल भुगतान में तीन गुना वृद्धि करना है।

'पेमेंट विजन 2025' के बारे मे

रिजर्व बैंक द्वारा 'पेमेंट्स विजन 2025' दस्तावेज जारी किया गया, जिसका लक्ष्य डिजिटल भुगतान में तीन गुना वृदि कर, भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावरहाउस के रूप में स्थापित करना है।

थीम

इसकी थीम 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई) है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और सस्ता ई-पेमेंट विकल्प प्रदान करना है।

दस्तावेज का विजन

1. डिजिटल भुगतान की भौगोलिक पहचान
2. भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मध्यवर्ती संस्थाओ का विनियमन
3. भुगतान क्षेत्र में बिगटेक और फिनटेक का विनियमन
4. अभी खरीदे,बाद मे भुगतान करे
5. डिजिटल भुगतान की संख्या में तीन गुना वृदि करना, डेबिट कार्ड के उपयोग में वृद्धि करना तथा नकदी के प्रचलन को कम करना है।

महत्व-

1. ग्लोबल लीडर- यह डिजिटल भुगतान क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। उदाहरण के तौर पर UPI का प्रयोग भूटान, नेपाल, सिंगापुर इत्यादि देशो मे हो रहा है।

2. डिजिटल समाज- यह कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर भारत का रूपांतरण है

3. वित्तीय समावेशन- यह अधिक से अधिक लोगो को डिजिटल भुगतान के दायरे मे लाकर, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगाद्य RBI के डाटा के अनुसार पिछले 3 वर्षो मे कुल डिजिटल भुगतान में 216% की वृद्धि हुई है।

4. उपयोग में आसानी और सुविधाजनक- यह उपयोगकर्ताओं को सुविधा के साथ किसी भी समय और कहीं भी सुलभ भुगतान हेतु सशक्त बनाएगा।

5. डाटा लोकलाईजेसन को बढ़ावा- जैसा की हम जानते है कि मौजूदा 4TH औद्योगिक क्रांति के दौर मे डाटा एक नयी करेंसी के रूप मे उभरा है। अत: भारत मे ही डाटा स्टोर होने से,भारत की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियां-

1. डिजिटल निरक्षरता- डेलॉयट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में डिजिटल साक्षरता 10% से कम है।

2. साइबर खतरे- डिजिटल भुगतान के बढ़ते तरीकों के साथ डिजिटल भुगतान से धोखाधड़ी में वृद्धि होगी। ऑनलाइन धोखाधड़ी, सूचना की चोरी, और मैलवेयर या वायरस के हमलों जैसे साइबर सुरक्षा जोखिमों के संपर्क में आने की संभावना भी बढ़ रही है।

3. डिजिटल भुगतान पर शुल्क- भारत के सामाजिक-आर्थिक दशा को देखते हुए, डिजिटल भुगतान पर शुल्क,इसके प्रयोग को हतोत्साहित करता है।

4. भू-राजनीतिक जोखिम- यह दस्तावेज उभरते भू-राजनीतिक जोखिमों को देखते हुए, घरेलू भुगतान प्रणालियों की रिंग-फेंसिंग के बारे में भी बात करता है, जिसमें भुगतान लेनदेन के घरेलू प्रसंस्करण को अनिवार्य करने की आवश्यकता भी शामिल है।

भुगतान विजन 2019-21 की उपलब्धियां-

भुगतान विजन 2021, प्रत्येक भारतीय को ऐसे ई-भुगतान विकल्पों तक जो सुरक्षित, मजबूत, सुविधाजनक, त्वरित और किफायती है, तक पहुंच प्रदान करती है। साथ ही प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और आत्मविश्वास के चार लक्ष्य भी निर्धारित करती है ।

इन लक्ष्यों को निम्नलिखित पहलों के माध्यम से पूरा किया गया है-

प्रतिस्पर्द्धा- नियामक सैंडबॉक्स का निर्माण, गैर-बैंक PSO के लिये केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS) की पहुंच, ऑफलाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा, भुगतान प्रणालियों के लिये 'ऑन टैप' प्राधिकरण, घरेलू भुगतान प्रणालियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, फीचर फोन-आधारित भुग. तान सेवाओं, भुगतान प्रणालियों के लिये स्व-नियामक संगठन के लिये ढांचा आदि।

लागत- रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम आदि में लेनदेन के लिये RBI द्वारा लगाए गए शुल्क में छूट।

सुविधा- 24X7X365 आधार पर NEFT, RTGS और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग

हाउस की उपलब्धता, असफल लेनदेन के संबंध में समाधान और मुआवजे के लिये टर्न-अराउंड-टाइम का सामंजस्य आदि

आत्मविश्वास-

भुगतान एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिये ढाँचा, आवर्ती लेनदेन के लिये ई-जनादेश, कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन और कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन आदि।

आगे की राह-

1. डिजिटल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना
2. मजबूत साइबर सुरक्षा कानून का निर्माण।
3. डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा

NOTES

2 सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर सलाहकार पैनल बनाया

शेयर बाजार नियामक, सेबी (SEBI) ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया है, जो ऐसे उपकरणों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें करेगी, जिसमें जारी करने में आसानी तथा घरेलू और वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपाय शामिल हैं। इस 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के वी कामथ करेंगे। इसके अलावा, समिति में बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (InvITs), रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs), वित्त के साथ-साथ कानूनी विशेषज्ञ और सेबी के शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल हैं। REITs और InvITs को हाइब्रिड प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वे भारतीय संदर्भ में अपेक्षाकृत नए निवेश साधन हैं लेकिन वैश्विक बाजारों में बेहद लोकप्रिय हैं। समिति को देश में हाइब्रिड प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विकास और नियमन से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देने का काम दिया गया है।

इसके अलावा, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की जरूरतों के संदर्भ में हाइब्रिड प्रतिभूतियों के उपयोग के परिदृश्यों की पहचान करेगा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकासशील उपायों की सिफारिशें करेगा।

इसके अलावा, सेबी ने अपनी अनुसंधान सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, जो पूंजी बाजार विनियमन अनुसंधान के लिए प्रासंगिक डेटाबेस के प्रचार, विकास, रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

सेबी के बारे में

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल, 1988 को एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (15/1992) के प्रावधान 30 जनवरी, 1992 को लागू हुए।

सेबी का उद्देश्य

जिस उद्देश्य के लिए सेबी की स्थापना की गई थी, वह एक ऐसा वातावरण प्रदान करना था जो संसाधनों को जुटाने और आवंटन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अभ्यास, ढांचा और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।

NOTES

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

1. इसरो ने फ्रेंच गुयाना के कौरू से भारत के संचार उपग्रह जीसैट-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 22 जून को फ्रेंच गुयाना के कौरू से संचार उपग्रह जीसैट-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के लिए इसरो द्वारा निर्मित जीसैट-24 को फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है।

जीसैट-24 एक 24-केयू बैंड संचार उपग्रह है जिसका वजन 4180 किलोग्राम है, जो डी.टीएच अनुप्रयोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कवरेज प्रदान करेगा। यह अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के बाद एनएसआईएल द्वारा किया गया पहला मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन था। अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की कंपनी NSIL ने पूरी सैटेलाइट क्षमता 'टाटा प्ले' को लीज पर दी है।

2. IIT मद्रास सेना प्रशिक्षण कमान के लिए 5G परीक्षण मंच स्थापित करेगा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) के साथ मिल. कर इंदौर के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई) में 5जी टेस्ट मंच स्थापित करेगा ताकि भारतीय सेना सीमा पर 5जी तकनीक का उपयोग कर सके। यह सहयोग भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रौद्यो. गिकी का उपयोग करने वाली प्रणालियों, उपकरणों को शामिल करने और एआई- आध ारित एल्गोरिदम के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इस साझेदारी से छात्रों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों को 5जी संचार में अनुसंधान करने और सैन्य अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

3. प्रधान मंत्री ने 'वाणिज्य भवन' का उद्घाटन किया और NIRYAT पोर्टल लॉन्च किया

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर - 'वाणिज्य भवन' का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान, पीएम ने एक नया पोर्टल - NIRYAT (व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात-निर्यात रिकॉर्ड) भी लॉन्च किया - जिसे भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है।

इंडिया गेट के पास निर्मित, वाणिज्य भवन को एक स्मार्ट इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें ऊर्जा की बचत पर विशेष ध्यान देने के साथ टिकाऊ वास्तुकला के सिद्धांत शामिल हैं। यह एक एकीकृत और आधुनिक कार्यालय परिसर के रूप में काम करेगा जिसका उपयोग मंत्रालय के तहत दो विभागों यानी वाणिज्य विभाग और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया जाएगा। NIRYAT पोर्टल सभी हितधारकों को वास्तविक समय डेटा प्रदान करके साइलो (भूमिगत कक्ष) को तोड़ने में मदद करेगा।

4. प्रधानमंत्री ने आईआईएससी, बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के परिसर में स्थित सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च (सीबीआर) का उद्घाटन किया।

सीबीआर के बारे में

सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को श्री क्रिस गोपालकृष्णन (इन्फोसिस लिमिटेड के सह- संस्थ. ापक) और श्रीमती सुधा गोपालकृष्णन के उदार उपहार के साथ एक स्वायत्त, गैर-लाभ. ाकारी अनुसंधान संगठन के रूप में स्थापित किया गया है ।

सीबीआर का अधिदेश स्वास्थ्य और रोग में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझने के लिए बुनियादी शोध करना है। सीबीआर का उद्देश्य मनोभ्रंश और अन्य उम्र से संबंधित मस्तिष्क विकारों के लिए तर्कसंगत उपचारों की खोज के प्राथमिक लक्ष्य के साथ अंतर-अनुशासनात्मक तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान के लिए केंद्रित अनुसंधान कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। सीबीआर ने वृद्ध आबादी में अनुभूति, आनुवंशिकी और मस्तिष्क इमेजिंग का व्यापक, दीर्घकालिक अनुदैर्ध्य अध्ययन शुरू किया है जिसमें रोगी और स्वस्थ व्यक्ति शामिल हैं।

5. नीति आयोग के नए सीईओ

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। वे मौजूदा सीईओ अमिताभ कांत की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 30 जून को पूरा होगा।

नीति आयोग क्या है?

1जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को स्थान दिया गया। इसकी प्रशासनिक संरचना इस प्रकार है-

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री

उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त

संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।

6. जी -7 द्वारा $ 600 बिलियन इन्फ्रा प्रोजेक्ट की घोषणा

जी -7 नेताओं ने रविवार को विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के लिए पांच वर्षों में निजी और सार्वजनिक धन में $600 बिलियन जुटाने और चीन के मल्टीट्रिलियन-डॉलर बेल्ट और रोड परियोजना का मुकाबला करने का वादा किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका कम और मध्यम आय वाले देशों में परियोजनाओं के लिए पांच वर्षों में अनुदान, संघीय धन और निजी निवेश में $200 बिलियन जुटाएगा जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के साथ-साथ वैश्विक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करने में मदद करेगा।

यूरोप चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्कीम के लिए एक स्थायी विकल्प बनाने के लिए इसी अवधि में 300 बिलियन यूरो ($317.28 बिलियन) जुटाएगा।

7. राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक

पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का महानिदेशक नियुक्त किया है। पंजाब कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता 31 मार्च 2024 तक इस पद पर रहेंगे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में-

राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। वर्ष 2008 के मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद एवं कुछ अन्य आपराधिक कृत्यों की जाँच के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए, NIA का गठन किया गया।

यह निम्नलिखित मामलों में अपराधों की जाँच और अभियोग चलाने की केंद्रीय एजेंसी है:

- भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध।
- परमाणु और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध।
- नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी।

हाल ही में वर्ष 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए संसद द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया। इस विधेयक में NIA को निम्नलिखित अतिरिक्त आपराधिक मामलों की भी जाँच करने की अनुमति देने का प्रावधान है-

- जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध
- प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री
- साइबर आतंकवाद
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, (Explosive Substances Act) 1908 के तहत अपराध।

इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा इसकी शाखाएँ हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में हैं।

8. भारत के सामने दोहरे घाटे की समस्या

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या के फिर से उभरने की चेतावनी दी, जिसमें कमोडिटी की ऊंची कीमतें और सब्सिडी का बोझ बढ़ने से राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों में वृद्धि हुई। यह पहली बार है जब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय फिसलन की संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर पूंजीगत व्यय को युक्तिसंगत बनाना न केवल विकास सहायक पूंजीगत व्यय की रक्षा के लिए बल्कि राजकोषीय फिसलन से बचने के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है।

मंत्रालय ने पहले संकेत दिया था कि यूक्रेन में युद्ध के बीच वैश्विक आपूर्ति की कमी के कारण वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का उर्वरक सब्सिडी बिल 1.05 ट्रिलियन रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले लगभग 2.5 ट्रिलियन रुपये तक बढ़ सकता है।

9. दक्षिण कोरिया ने दूसरे प्रयास में स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया

दक्षिण कोरिया ने अपने दूसरे प्रयास में 21 जून को अपना पहला घरेलू रूप से निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। इसके पूर्व किये गए प्रक्षेपण में लिफ्टऑफ के बाद कक्षा में पेलोड स्थापित करने में विफल रहा था। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एक सफल प्रक्षेपण दक्षिण कोरिया की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगा, लेकिन यह भी साबित करेगा कि उसके पास प्रतिद्वंद्वी उत्तर कोरिया के साथ विवाद के बीच अंतरिक्ष-आधारित निगरानी प्रणाली और बड़ी मिसाइलों का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां हैं।

पिछले अक्टूबर में पहले प्रयास में, रॉकेट का डमी पेलोड 700 किमी (435 मील) की वांछित ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन कक्षा में प्रवेश नहीं किया क्योंकि रॉकेट का तीसरा चरण योजना से पहले जल गया था।

दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दक्षिण कोरिया विश्व बाजारों में सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोबाइल और स्मार्टफोन का मुख्य आपूर्तिकर्ता है। लेकिन इसका अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम अपने एशियाई पड़ोसियों चीन, भारत और जापान से पीछे है।

10. आईओसी ने ''सूर्य नूतन'' का अनावरण किया

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने एक स्थिर, रिचार्जेबल और इनडोर खाना पकाने के स्टोव का अनावरण किया है जो कि रसोई में हमेशा खाना पकाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करता है। स्टोव, जिसमें एक बार की खरीद लागत आती है और जिसका रखरखाव शून्य है, को जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। चूल्हे का नाम सूर्य नूतन रखा गया है,

सूर्य नूतन के बारे में

सूर्य नूतन, स्टोव सौर कुकर से अलग है क्योंकि इसे धूप में नहीं रखना पड़ता है। इसे फरीदाबाद में IOC के अनुसंधान और विकास प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है, यह हमेशा रसोई में रहता है और एक केबल बाहरी या छत पर रखे PV पैनल के माध्यम से कैप्चर की गई सौर ऊर्जा को वहन करती है।

यह सूर्य से ऊर्जा एकत्र करता है, इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए हीटिंग अवयवों के माध्यम से गर्मी में परिवर्तित करता है, थर्मल ऊर्जा को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध थर्मल बैटरी में संग्रहीत करता है और इनडोर खाना पकाने में उपयोग के लिए ऊर्जा को पुनः परिवर्तित करता है। कैप्चर की गई ऊर्जा न केवल चार लोगों के परिवार की दिन की खाना पकाने की जरूरतों को पूरा करती है बल्कि रात के भोजन को भी पूरा करती है।

11. भारत वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चौथे स्थान पर

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जून में जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में चौथे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है जिसमें पिछले पांच वर्षों में भारत की 11 प्रतिशत सोने की आपूर्ति ''पुराने सोने'' से हुई है।

उच्च पुनर्चक्रण सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव, भविष्य में सोने की कीमत की उम्मीदों और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। भारत में सोने का पुनर्चक्रण 440 अरब रुपये का उद्योग है।

सोने के पुनर्चक्रण के तीन प्रमुख स्रोत आभूषण, विनिर्माण स्क्रैप और औद्योगिक स्क्रैप हैं। पुराने आभूषण स्क्रैप भारत में पुनर्चक्रण के सबसे बड़े स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी कुल हिस्सेदारी लगभग 85 प्रतिशत है।

औद्योगिक स्क्रैप इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग हो चुके उत्पादों का जैसे मुद्रित सर्किट बोर्ड, मोबाइल फोन, कनेक्टर और संपर्क बिंदुओं से उत्पन्न होता है। यह औद्योगिक सेगमेंट कुल भारतीय कबाड़ आपूर्ति का 5 प्रतिशत से भी कम है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने चीन का मुकाबला करने के लिए 'पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक' (पीबीपी) पहल शुरू की। पीबीपी प्रशांत महासागर के द्वीपों का सहयोग करेगा और इस क्षेत्र में राजनयिक, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देगा।

2. रोहिल (खंडेला तहसील) सीकर राजस्थान में मिले यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान तीसरा राज्य है जहां यूरेनियम पाया गया है।

3. रूस 1918 के बाद पहली बार विदेशी ऋण चूका पाने में नाकाम रहा।

4. संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हर साल 27 जून को ''अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस'' मनाया जाता है। इस वर्ष एमएसएमई दिवस ''लचीलापन और पुनर्निर्माण: निरन्तर विकास के लिए एमएसएमई'' विषय के तहत मनाया गया।

5. ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सिडनी मैकलॉघलिन ने यूजीन के ओरेगन में यू.एस. चौंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ कर 51.41 सेकंड में फाइनल जीत लिया।

6. टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ जल निकाय (बैकवाटर क्षेत्र), में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है, जिसकी स्थापित क्षमता 101.6 मेगावाट है।

7. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक 1973 रो बनाम वेड के फैसले को पलट दिया है, जिसने महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता दी थी।

8. नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम ''स्वास्थ्य और मानवीय संकट में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान'' है।

9. सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर का विस्तार करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इस उपकर को 1 जुलाई, 2017 को लागू होने के पांच साल बाद 30 जून, 2022 को समाप्त होना था।

10. बांग्लादेश की रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है।

11. केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु (कर्नाटक) को वर्ष 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है।

12. संयुक्त राष्ट्र (UN) विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाता है। इस वर्ष की थीम -''जो भी कहीं भी और जब भी मौजूद हो उसे सुरक्षा मांगने का अधिकार'' है।

13. गोवा में "धरोहर" नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन, वित्त मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया गया ।

14. 19वीं शांगरी-ला वार्ता दो साल बाद सिंगापुर में आयोजित की गई। यह शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS) द्वारा आयोजित किया जाता है।

15. कंबोडिया की मेकांग नदी में दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी (फ्रेश वॉटर) की मछली 'स्टिंगरे' मिली है।

16. हरियाणा स्थित आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन (एनआरसी) ने जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू COVID-19 वैक्सीन ''एनोकोवैक्स (Anocovax)'' लॉन्च किया।

17 चीन ने अपना तीसरा विमानवाहक पोत 'फुजियान' लॉन्च किया, जो देश का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी नौसैनिक पोत है।

18. गुजरात सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए ''मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना'' प्रारंभ की गयी।

19. 'स्कालर्जंग रिगजिन' अन्नपूर्णा चोटी, नेपाल पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बनें।

20. वैज्ञानिकों ने ग्वाडेलोप में एक दलदल में दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात जीवाणु की खोज की है। लगभग 1 सेमी लंबा, थियोमार्गरीटा मैग्निफा, अन्य सभी ज्ञात विशाल जीवाणुओं की तुलना में लगभग 50 गुना बड़ा है और नग्न आंखों से दिखाई देता है।

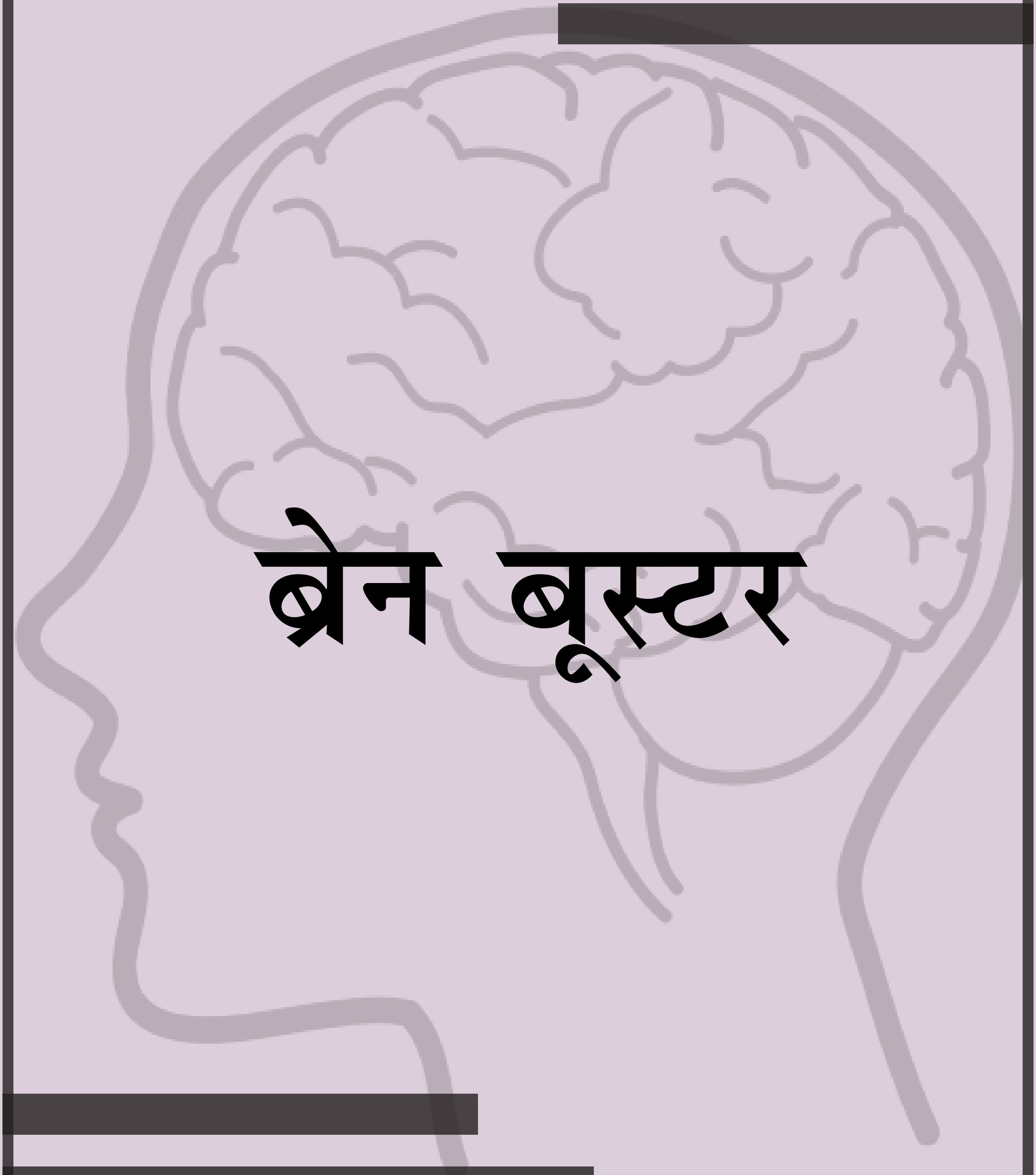

ब्रेन बूस्टर

इंटीग्रल कोच फैक्टरी

परिचय

सवारी डिब्बा कारखाना जिसे संक्षिप्त में आईसीएफ भी कहते हैं, स्वतंत्र भारत की सबसे पुरानी उत्पादन इकाइयों में एक है। इसका उद्घाटन 2 अक्तूबर 1955 तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने चेन्नई में किया था।

1. उत्पादन

- आईसीएफ ने अपनी स्थापना से 65000 से अधिक डिब्बों का निर्माण किया है।
- 2019-20 में फैक्टरी ने अभी तक का सर्वाधिक 4166 डिब्बो का उत्पादन किया था जिससे यह विश्व में रेलवे सवारी डिब्बा के उत्पादन में सबसे बड़े निर्माता के रूप में उभरी है।
- महामारी के समय 2021-22 में इसने 3101 कोचों का निर्माण करके अपनी महत्ता बताया है।

2. वैश्विक उपस्थिति

- सवारी डिब्बा कारखाना विभिन्न देशों जैसे थाईलैंड, बर्मा, ताईवान, जाम्बिया, फिलीपिंस, तंजानिया, यूगाण्डा, वियतनाम, नाइजीरिया, नेपाल, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, मलेशिया, अंगोला और श्रीलंका को अब तक 800 से भी अधिक कोचों का निर्यात कर चुका है।

3. हरित पहल

- सवारी डिब्बा कारखाना ने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अनेक कदम उठाया है। जैसे सडिका के क्षेत्र में हरे-भरे बाग-बगीचों का निर्माण, बिजली के उत्पादन के लिए पवन चक्कियों और सोलर पैनलों की स्थापना आदि।
- सवारी डिब्बा कारखाना 'जीरो डिस्चार्ज फैक्टरी' और 'ग्रीन वर्कशाप' भी है।
- सवारी डिब्बा कारखाना ने अपने परिसर में ग्रीन-हाउसों की स्थापना की है जिसमे पर्यावरण संरक्षण वाले पौधे लगाये गये हैं। इस परिसर में 'पाली हाऊस' भी है जहाँ पौधों और वृक्षों के लिए आवश्यक बीज बोने का काम चलता है।

- सवारी डिब्बा कारखाना, भारतीय रेल का ऐसा संगठन बन चुका है जिसने पूर्णतः न्यूट्रालाइज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन सिस्टम और कार्बन नेगटिव स्टेटस की उपलब्धि हासिल की है।

4. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

- सवारी डिब्बा कारखाना परिसर में महिला सशक्ति की 9 टीमें हैं जिनमें कुल 130 महिलाएं हैं।
- विश्व के अग्रणी एवं सबसे बडे रेल कोच निर्माता के रूप में प्रसिद्ध, इस कारखाने में महिलायें वो कार्य कर रही हैं जोकि केवल पुरुष ही करते थे।
- वेल्डिंग, फिटिंग, हार्नेसिंग, आर्क वेल्डिंग, मोटरों की पेंटिग और सिंगल फेज मोटर वाइन्डिंग जैसे कठिन कार्यों को इस टीम की महिलाएँ संभाल रही हैं।

5. ट्रेन-18 (वंदे भारत एक्सप्रेस)

- वर्ष 2018-19 में सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन -18 का उत्पादन किया गया जोकि नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती है।
- "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने वाला यह कारखाना 80 प्रतिशत से अधिक उत्पाद पूर्णतः घरेलू होता है।
- पहला प्रोटोटाइप ट्रेन-18 का उत्पादन 18 महीने के रिकार्ड समय में हुआ जोकि 140 सेकेण्ड में 160 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है।
- रेलवे इस गति को 250 किमी/घंटा तक करने की योजना बना रहा है जिसके लिए रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी।
- अगस्त, 2023 तक 75 ट्रेन के निर्माण के अतिरिक्त इस वर्ष के बजट में पचास हजार करोड़ रूपये आवंटित किया गया है ताकि आने वाले तीन वर्षों में 400 वन्दे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा सके।
- अभी 16 डिब्बे वाली इस ट्रेन को बनाने में 106 करोड़ रूपये का खर्च आता है।

6. हाल की उपलब्धियां

- आईसीएफ ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम के तहत ग्रीनको गोल्ड स्तर के पुरस्कार का प्रतिष्ठित प्रमाण प्राप्त किया है।
- आईसीएफ ने रेलवे वाहनों और घटकों के निर्माता के अंतर्गत विशिष्ट वेल्डिंग मानक के लिए प्रतिष्ठित ईएन 15085 प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया था। आईसीएफ ऐसा प्रमाणन हासिल करने वाली पहली भारतीय रेलवे उत्पादन इकाई है।

भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन

1. चर्चा में क्यों?

केंद्र ने 1 जुलाई से 'एकल उपयोग वाले प्लास्टिक' के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी, और अब उन वस्तुओं को परिभाषित किया है जिन्हें 1 जुलाई से प्रतिबंधित किया जाएगा।

2. सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में

- एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक ऐसे सामान हैं जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन-आधारित रसायनों (पेट्रोकेमिकल्स) से बने होते हैं और उपयोग के तुरंत बाद-अक्सर, केवल मिनटों में निपटाने के लिए होते हैं।
- सिंगल-यूज प्लास्टिक, निर्मित और उपयोग किए गए प्लास्टिक के उच्चतम शेयरों में से एक है - वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, कचरा बैग, खाद्य पैकेजिंग आदि तक।
- 1950 के दशक से, 8.3 बिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया है, और इसका आधा केवल पिछले 15 वर्षों में ही उत्पादित हुआ है।

3. सिंगल यूज प्लास्टिक खराब क्यों है?

- हम दुनिया भर में हर साल 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, जिसमें से आधा एकल-उपयोग वाली वस्तुओं के लिए है। यह लगभग पूरी मानव आबादी के वजन के बराबर है।
- विश्व स्तर पर उत्पादित सभी प्लास्टिक का एक तिहाई हिस्सा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का है, जिसमें 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित होते हैं।
- सिंगल-यूज प्लास्टिक 2019 में दुनिया भर में छोड़े गए अधिकांश प्लास्टिक, 130 मिलियन मीट्रिक टन के लिए जिम्मेदार है, जो सभी को जला दिया जाता है, लैंडफिल में दफन कर दिया जाता है या सीधे पर्यावरण में फेंक दिया जाता है।
- प्लास्टिक वास्तव में विघटित नहीं होता है; वे बस टूट जाते हैं, समय के साथ, सूरज और गर्मी धीरे-धीरे प्लास्टिक को माइक्रो प्लास्टिक में बदल देते हैं।
- सूक्ष्म प्लास्टिक पानी में चला जाता है, जिसे वन्यजीव खा जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं।
- माइक्रो प्लास्टिक ने अंटार्कटिक महाद्वीप और मारियाना ट्रेंच के तल तक अपना रास्ता बना लिया है।

4. प्रतिबंधित आइटम

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रतिबंधित आइटम ईयरबड हैं; गुब्बारे की छड़ें; कैंडी और आइसक्रीम की छड़ें; प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे सहित कटलरी आइटम; मिठाई के बक्से; निमंत्रण कार्ड; सिगरेट पैक; 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर; और सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन।
- मंत्रालय ने सितंबर 2021 में 75 माइक्रोन से कम के पॉलीथिन बैग पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था, जो पहले के 50 माइक्रोन की सीमा को बढ़ाता था।
- दिसंबर से 120 माइक्रॉन से कम के पॉलीथिन बैग पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर भी पूर्ण प्रतिबंध है।

5. प्रतिबंध लागू करना

- केंद्र की ओर से सीपीसीबी द्वारा प्रतिबंध की निगरानी की जाएगी। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) नियमित रूप से केंद्र को रिपोर्ट करेंगे।
- प्रतिबंधित वस्तुओं में लगे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति न करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं।
- स्थानीय प्राधिकरणों को इस शर्त के साथ नए वाणिज्यिक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया है कि उनके परिसर में एसयूपी आइटम नहीं बेचे जाएंगे, और मौजूदा वाणिज्यिक लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे यदि वे इन वस्तुओं को बेचते पाए जाते हैं।
- प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है - जो 5 साल तक की कैद, या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है ।

6. सिंगल यूज प्लास्टिक से निपटने वाले अन्य देश

- बांग्लादेश 2002 में प्लास्टिक की पतली थै. लियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना।
- न्यूजीलैंड जुलाई 2019 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बन गया।
- चीन ने 2020 में चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध जारी किया।
- जुलाई 2019 तक, 68 देशों में अलग. -अलग डिग्री के प्रवर्तन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है।

7. सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाव

- खरीदारी करते समय हमेशा एक पुनः प्रयोज्य बैग का प्रयोग करें।
- अपने आप को शिक्षित करें।
- पुनः प्रयोज्य वस्तुओं की खरीद करें।
- एस आई पी के उपयोग को कम करने के लिए दूसरों को शिक्षित करें।
- दूसरों को सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरनाक प्रभावों से अवगत कराएं ।
- थोक में खरीदें करें ,स्नैक पैक जैसे व्यक्तिगत रूप से पैक किए गए सामान से बचें।

विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

1. खबरों में क्यों?

- 17 जून को, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों ने वैश्विक वैक्सीन इक्विटी प्राप्त करने के लिए पेटेंट नियमों में ढील देने हेतु बारहवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी12) में शिरकत की ताकि खाद्य, मत्स्य पालन और ई-कॉमर्स के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर बातचीत कर सके।
- इसके अतिरिक्त डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो इवेला ने इसे जिनेवा पैकेज के रूप में संदर्भित किया। इस बैठक में भारत ने भी कुछ क्षेत्रों के संबंध में सफलताएँ प्राप्त की।

2. विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हर दो साल में एक बार होता है और किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय ले सकता है।
- आईएमएफ या विश्व बैंक जैसे अन्य संगठनों के विपरीत, विश्व व्यापार संगठन निदेशक मंडल या किसी संगठनात्मक प्रमुख को शक्ति नहीं देता है।
- विश्व व्यापार संगठन में सभी निर्णय सामूहिक रूप से और विभिन्न परिषदों और समितियों में सदस्य देशों के बीच आम सहम. ति के माध्यम से किए जाते हैं।
- इस साल का सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था।

3. कृषि पर विवाद

- इस विषय पर समझौता भारत के लिए विशेष महत्व रखते हैं।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति का उल्लेख करते हुए, भारत ने पहले कहा था कि उसने कार्यक्रम के तहत खरीद के लिए कभी भी निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया।
- सभी पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि सदस्य देश डब्ल्यूएफपी के मानवीय उद्देश्यों के लिए खरीदे गए खाद्य पदार्थों पर निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाएंगे।
- समझौते का केंद्रीय आधार जरूरतमंद लोगों को विशेष रूप से मानवीय आपात स्थितियों में भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करना था।

4. मात्स्यिकी संबंधी समझौतों पर कोई सहमति नहीं

- भारत ने अवैध, गैर-सूचित और अनियमित मछली पकड़ने में लगे लोगों को प्राप्त हो रही सब्सिडी समाप्त करने पर एक समझौता करने में सफल रहा।
- अत्यधिक मछली वाले स्टॉक के लिए सब्सिडी जारी रखने का एकमात्र अपवाद तब होगा जब उन्हें जैविक रूप से टिकाऊ स्तर पर पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक समझा जाता है।
- इसके अलावा समझौते में यह माना गया कि विकासशील या कम विकसित देशों द्वारा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) के भीतर मछली पकड़ने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर कोई सीमा नहीं होगी।

5. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर अधिस्थगन (Electronic Transmission)

- सदस्य देश इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन (ET) पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर मौजूदा स्थगन को MC 13 तक बढ़ाने पर सहमत हुए जो दिसंबर 2023 में होने वाला है।
- 105 देशों जिनमें यू.एस., यूके, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान शामिल हैं, ने स्थगन का विस्तार करने की मांग की थी जबकि भारत और दक्षिण अफ्रीका इसके विरोध में थे।
- मोटे तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में संगीत, ई-किताबें, फिल्म, सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम जैसी ऑनलाइन डिलीवरी शामिल हैं।
- सीमा शुल्क क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक पूंजी प्रवाह प्रदान करते हैं और बदले में, कम आय और विकासशील देशों में विशेष रूप से उच्च डिजिटल विभाजन को कम करने का प्रयास करते हैं।

6. पेटेंट छूट पर चर्चा

- सदस्य देशों ने पेटेंट ऑनर की सहमति के बिना किसी सदस्य देश द्वारा COVID-19 टीकों के उत्पादन के लिए पेटेंट की विषय वस्तु के उपयोग को अनुमति प्रदान की।
- इसके अलावा, यह सदस्य देशों को घरेलू बाजारों और सदस्य देशों को किसी भी संख्या में टीकों की आपूर्ति के लिए निर्यात प्रतिबंध सहित आवश्यकताओं में छूट प्रदान करता है।
- हालाँकि, यह समझौता आर्थिक रूप से गरीब देशों के लिए बहुत कम, बहुत देर से आया है क्योंकि कई निम्न विकसित देशों (LDCs) को अब लगभग तीन साल पहले आयी महामारी से निपटने के अपने प्रयासों में नुकसान उठाना पड़ा है।
- अगले छह महीनों के भीतर, सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे COVID-19 डायग्नोस्टिक्स और चिकित्सीय उत्पादन एवं आपूर्ति को कवर करने के लिए समझौते के दायरे को बढ़ाने पर भी निर्णय लेंगे।

5जी नीलामी

1. खबरों में क्यों?

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को हुई बैठक में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अपनी मंजूरी दी जिसका उपयोग 5 जी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।
- जुलाई के अंत में आयोजित नीलामी के दौरान 20 वर्ष की वैधता अवधि के साथ कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए रखा जाएगा।

2. 5जी तकनीक के बारे में

- 5 जी अगली पीढ़ी की सेलुलर तकनीक है जो बहुत धीरे लेटेंसी (लेटेंसी अपने स्रोत और गंतव्य के बीच यात्रा करने के लिए डेटा की मात्रा है) के साथ तेज और अधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी।
- 5जी के साथ निर्धारित मानकों के अनुसार, मौजूदा 4जी नेटवर्क पर लगभग 25 एमबी/से. की तुलना में 5 जी नेटवर्क की स्पीड 2-20 जीबी/से. की सीमा में होने की उम्मीद है।
- भारत में, हालांकि, 4जी की गति औसतन लगभग 6-7 एमबी/से. है जोकि धीरे-धीरे गति पकड़ता है।
- यह उपलब्ध बैंडविड्थ और उन्नत एंटीना प्रौद्योगिकी के कारण वायरलेस सिस्टम पर प्रसारित डेटा की मात्रा में वृद्धि को सक्षम करेगा।

3. 5 जी का वाणिज्यिक रोलआउट

- दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार होने के बावजूद भारत में यह सेवा अभी संचालित नहीं हो सकी है।
- ऐसा कहा जाता है कि 5जी की तैनाती इस साल अगस्त-सितंबर से शुरू होने की संभावना है और साल के अंत तक लगभग 20-25 शहरों में सेवा शुरू हो सकती है।
- विशेषज्ञों और विश्लेषकों को उम्मीद है कि अगले दो से तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से देश भर में 5जी का क्रमिक रोलआउट शुरू हो जायेगा।

4. 5 जी के लाभ

- 5 जी आने से आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) और मशीन से मशीन संचार जैसी उभरती हुई तकनीकों की रीढ़ बनने की उम्मीद है जिससे अनुप्रयोगों और सेवाओं की एक बड़ी रेंज बढ़ सकेगी।
- यह उम्मीद की जाती है कि 5जी तकनीक के साथ, उपभोक्ता कुछ ही सेकंड में डेटा भारी सामग्री जैसे 8के मूवी और बेहतर ग्राफिक्स के साथ गेम डाउनलोड करने में सक्षम होंगे।
- यह उद्योग, कृषि, संस्थानों, अस्पतालों और राजमार्गों जैसी ढांचागत गतिविधियों में सुधार करके अर्थव्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों के कार्य कुशलता में वृद्धि करेगा।
- 5 जी से 2035 तक भारत में $1 ट्रिलियन का आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है।

5. 5 जी से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- दो मुख्य मुद्दे हैं;
  - स्पेक्ट्रम के लिए उच्च आरक्षित मूल्य
  - कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम का प्रत्यक्ष आवंटन।
- सोचनीय बात यह है कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की तुलना में 5 जी तकनीक का उद्योग में अधिक उपयोग है क्योंकि यह बहुत ही लागत प्रभावी तकनीक है। उदाहरण के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम (युग्मित) के एक ब्लॉक की लागत 196 बिलियन (यूएस $2.5 बिलियन) होगी। अतः इसके मूल्य को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहा है।
- कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के प्रत्यक्ष आवंटन की अनुमति देने पर, सरकार ने तर्क दिया है कि इस कदम से उद्योग 4.0 में अनुप्रयोगों जैसे मशीन से मशीन संचार, आईओटी, एआई में ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, कृषि, ऊर्जा में नवाचारों की एक नई लहर को बढ़ावा मिलेगा।
- उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क तक पहुंचने के लिए 5 जी सक्षम उपकरणों को अपडेट करने की आवश्यकता होगी, यदि वे पहले से एक का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

6. निष्कर्ष

जब प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और विश्व शक्तियां अपनी तकनीकी को उन्नत कर रही हैं ताकि वे अपने लोगों के लिए उच्च विकास और बेहतर जीवन शैली प्राप्त कर सकें, तो भारत जो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है बहुत दिनों तक अनसुना नहीं कर सकता है। हमें प्रौद्योगिकी के मामले में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए इस पर काम करना होगा।

क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करना

1. चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई द्वारा प्रवर्तित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा जारी किए गए रुपे क्रेडिट कार्ड पहले सक्षम होंगे, और सिस्टम के विकास के बाद उपलब्ध हो जाएंगे।

1. एकीकृत भुगतान इंटरफेस के बारे में?

- UPI NPCI द्वारा विकसित एक तत्काल रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली है। यह इंटरफेस इंटर-बैंक पीयर-टू-पीयर (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।
- एनपीसीआई द्वारा प्रबंधित यूपीआई को पहली बार 2016 में पेश किया गया था।
- यह तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) का एक उन्नत संस्करण है।
- UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में, कई बैंकिंग सुविधाओं को मर्ज करने, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक हुड में शक्ति प्रदान करती है।

3. क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने की आवश्यकता

- यूपीआई वर्तमान में राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), आईएमपीएस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), रुपे आदि सहित एनपीसीआई संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है।
- यूपीआई समय के साथ भारत में भुगतान का एक लोकप्रिय माध्यम बन गया है, जिसके प्लेटफॉर्म पर 26 करोड़ से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता और पांच करोड़ व्यापारी हैं।
- मई 2022 में, इंटरफेस के माध्यम से 10.4 लाख करोड़ की राशि के लगभग 594 करोड़ लेनदेन संसाधित किए गए।
- वर्तमान में, यूपीआई उपयोगकर्ताओं के डेबिट कार्ड के माध्यम से बचत/चालू खातों को जोड़कर लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।

3. इस कदम का महत्व

- इस व्यवस्था से ग्राहकों को भुगतान के लिए एक अतिरिक्त अवसर मिलने की उम्मीद है और इस प्रकार सुविधा में वृद्धि होगी।
- क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने का प्रस्ताव क्रेडिट कार्ड की पहुंच और उपयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए किया गया है।
- इससे अधिक मर्चेंट साइटों पर लेनदेन और स्वीकृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- जो लोग आम तौर पर विभिन्न वित्तीय विशेषाधिकारों के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पसंद करते हैं, वे अब यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं।
- वर्तमान में, कई व्यापारियों के पास विशेष रूप से अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट कार्ड पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल नहीं हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण संख्या में क्यूआर कोड आधारित यूपीआई स्वीकृति सुविधा है। अब, वे भी बिना PoS डिवाइस के UPI के माध्यम से क्रेडिट भुगतान स्वीकार कर सकेंगे।
- क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने से छोटे आकार के भुगतानों में ऐसे कार्डों के उपयोग में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करेगा।
- वर्तमान में प्रति लेनदेन औसत टिकट आकार 1,600 है जबकि क्रेडिट कार्ड में यह 4,000 है। इसलिए, नए विकास के साथ यूपीआई लेनदेन टिकट का आकार लगभग 3,000 से 4,000 तक जाने की संभावना है।

5. चुनौतियां

- यह स्पष्ट नहीं है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) कैसे लागू होगा।
- वीजा और मास्टरकार्ड जैसे विदेशी कार्ड जारीकर्ताओं के पास क्रेडिट कार्ड नेटवर्क व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा है, शुल्क का एक हिस्सा उन्हें जाता है।
- भारत सरकार ने स्वदेशी रुपे कार्ड प्रणाली को बढ़ावा देने की अपनी मंशा दिखाई है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या यह वास्तव में व्यापारियों के लिए विदेशी जारीकर्ताओं से क्रेडिट कार्ड वाले उपयोगकर्ताओं से भुगतान स्वीकार करने के लिए अधिक किफायती साबित होता है।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कामर्स

1. चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारत सरकार ने अपना ई – कामर्स कंपनी शुरू किया है ताकि अमेजॉन और वालमार्ट जैसे प्रभावशाली और दिग्गज कंपनियों के एकाधिकार को कम करते हुए लोगों को एक वैकल्पिक व्यवस्था दिया जा सके।
- इसे डिजिटल कामर्स हेतु ओपन नेटवर्क (ONDC) नाम दिया गया है।

2. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कामर्स

- यह एक गैर – लाभकारी कंपनी है जिसका नेटवर्क सभी उत्पादों एवं सेवाओं को सभी ई – कामर्स से सबंधित एप्लिकेशन के नेटवर्क पर सक्षम बनाने का कार्य करेगा।
- इसका उद्देश्य है कि आने वाले दो वर्षों में भारतीय उपभोक्ताओं के डिजिटल क्रय का 25% मार्केट आकर्षित करना जोकि 135 करोड़ लोगों के 8% के बराबर होगा।
- इसके अतिरिक्त सरकार आशान्वित है कि आने वाले पांच वर्षों में 90 करोड़ खरीद. कर्ता (BUYERS) और 12 लाख विक्रयकर्ता (SELLERS) इस प्लेटफॉर्म पर साइन अप करेंगे जिससे कुल सकल व्यापार 48 बिलियन डॉलर का होगा।
- सरकार ने उपलब्ध आकंड़ों की गणना करके आकलन किया है कि ई – कामर्स मार्केट का कुल सकल व्यापार 2021 में 55 बिलियन डॉलर था जिसमें तेजी से वृद्धि हो रही है और यह इस दशक के अतं तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है जोकि पाकिस्तान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर होगा।
- वर्तमान समय में अमेजॉन और वालमार्ट की फ्लिपकार्ट कुल मार्केट का लगभग 60% को कंट्रोल करते हैं।

3. इकॉनोमी बूस्ट करने का उद्देश्य

- मौजूदा प्लेटफॉर्म भूमिगत कक्ष (SILOS) होकर और सख्त नियत्रंण में कार्य करता है जिससे कुछ छोटे प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं। परन्तु इससे उम्मीद की जा रही है कि प्रति स्पर्धा समावेशी होगी जिससे स्टार्ट अप के नवीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- डिजिटल कामर्स हेतु ओपन नेटवर्क लोजिस्टिक D1 फर्म और अन्य प्लेयर को एक साथ लाएगा ताकि दोनों एक साथ सहमति या समझौते के फलस्वरूप क्रेता – विक्रेता में सामजंस्य बना रहे।
- इसका फोकस भारतीय भाषाओं में एप्लिकेशन के माध्यम से छोटे व्यापारी और ग्रामीण उपभोक्ता पर होगा।
- यह प्लेटफॉर्म कुछ चुनिन्दा विक्रेताओं के अवसरों को सीमित करेगा ताकि सभी को समान अवसर प्रदान किया जा सके।
- यह उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता कंपनी के बारे में जागरूक करेगा जिसके लिए रेटिगं को सभी नेटवर्क पर दिखाया जायेगा।
- यह प्लेटफॉर्म बढ़ा चढ़ाकर मार्जिन लेने वाली कीमतों को समय के साथ कम करेगा ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अतंर्गत सर. कार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु कई पहलुओ को शुरू किया है जैसे– उमंग , स्टार्ट अप इंडिया, भीम इत्यादि।
- सरकार ने भारत में 5जी फाइबर नेटवर्क के जाल बिछाने हेतु बहुत बड़े स्तर पर निवेश करने का फैसला किया है।

4. चुनौतियाँ

- कंपनी ने केवल अधिक से अधिक लाखों छोटे व्यापारियों को आकर्षित करने का उद्देश्य रखा है जोकि प्रायः तकनीकी फ्रेंडली नहीं होते हैं।
- अतः सरकार को एक बड़े स्तर पर एक प्रशिक्षण अभियान चलाना होगा ताकि उनको बोर्ड पर लाया जा सके।
- छोटे व्यापारियों के पास संसाधनों और उनकी मात्रा में कमी के कारण बहुत नुकसान होगा जब बड़ी – बड़ी कम्पनियाँ जैसे– अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने सामानों पर अधिकतम छूट ऑफर करेंगे।

5. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- जैसा कि उपभोक्ता से संबंधित विवादों के निवारण हेतु आयोग का नियम है कि रूपये 5 लाख तक के केस दायर करने की कोई फीस नहीं होगी।
- ई – कामर्स प्लेटफॉर्म को किसी भी उपभोक्ता के शिकायत की रशीद को 48 घंटे के अदंर संज्ञान में लेना होगा।
- सभी ई – कामर्स प्रदाताओं को कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को बताने की जरुरत होगी जैसे – सामानों की वापसी, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, शिपमेंट और डिलीवरी से सम्बधिंत जानकारी, भगुतान का रूप (MODE OF PAYMENT), शिकायत निवारण तंत्र आदि।

6. निष्कर्ष

- डिजिटल माध्यम से व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने में इंटरनेट ने बहुत सहायता किया है जिसमें ई – कॉमर्स भी एक सर्वाधिक प्रचलित प्लेटफॉर्म है।
- बिना किसी शक के ई – कॉमर्स अपने समाज का एक प्रमुख अंग बन गया है।
- आज के समय में ई – कॉमर्स सचूना तकनीकी का मुद्दा न होकर पूरी प्रणाली को देख रहा है।

भारत का राष्ट्रपति

1. खबरों में क्यों?

• हाल ही में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया।

• राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है (अनुच्छेद 52) और वह देश का पहला नागरिक भी होता है।

• वह उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी के साथ संघ की कार्यपालिका का हिस्सा है।

2. राष्ट्रपति का चुनाव

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होगा।

• यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है।

• चुनाव प्रक्रिया गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है।

• भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनावों हेतु इलेक्टोरल कॉलेज में निम्न निर्वाचित सदस्य शामिल हैं:

• लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य

• राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

• केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य

• राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। वह पुनः निर्वाचित हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है (अनुच्छेद 57)।

3. राष्ट्रपति की योग्यता (अनुच्छेद 58)

• वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

• उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए।

• लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

• वह लाभ के किसी पद पर न हो।

• अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कहता है जबकि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है।

4. राष्ट्रपति की शक्तियाँ: कार्यकारी शक्तियाँ

• भारत सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही उसके नाम पर जानी जाएगी ।

• वह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है।

• वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित लोगों की नियुक्ति करता है:

• भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)

• मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त

• संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य

• राज्य के राज्यपाल

• भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य।

• वह राष्ट्रीय आयोगों जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति करता है।

• वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है।

5. विधायी शक्तियां

• वह संसद सत्र को बुलाता है, उसका सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग करता है।(अनु. 85)

• गतिरोध की स्थिति में वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। (अनु. 108)

• वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र संसद को संबोधित करता है।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।

5. न्यायिक शक्तियां

• वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है।

• वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, हालांकि, दी गयी सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं हैं। (अनु.143)

• उसे अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।

7. अन्य शक्तियां

• राष्ट्रपति के पास कुछ वित्तीय शक्तियां हैं जैसे धन विधेयक पर पूर्व सिफारिश जरूरी है, संसद के समक्ष केंद्रीय बजट रखने की अनुमति देता है और वह हर पांच वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है।

• राष्ट्रपति थल सेना, नौसेना और वायु सेना जैसे रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है।

उसके पास तीन प्रकार की आपात शक्तियाँ हैं जैसे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 और 365 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल।

• राष्ट्रपति के पास राजनयिक शक्तियां हैं। उदाहरण के लिए संसद द्वारा अनुमोदित प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत उसके नाम से जाना जाता है।

मुख्य परीक्षा विशेष

भारतीय समाज, कला और संस्कृति एवं भारतीय इतिहास

1. भारत में पारिवारिक संरचना पर वैश्वीकरण के प्रभावों का आकलन करें।

उत्तर:

वैश्वीकरण का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृतियों के वैश्विक एकीकरण से है। चूँकि परिवर्तन किसी भी समाज की एक मूल विशेषता है। अतः भारतीय समाज भी विभिन्न कालखण्डों में विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर परिवर्तनशील रहा है।

- वैश्वीकरण के कारण भारत की पारिवारिक संरचना में बहुआयामी परिवर्तन आए हैं। जिसमें दो महत्वपूर्ण आयाम हैं-परिवार के आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन तथा पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन।

परिवार के आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन-

- वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसी अवधारणाएँ उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारत में भी रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ जो लिंग-भेद से मुक्त था। इसलिए महिला, पुरूष, बच्चों, वृद्धों सभी के लिए आय के स्रोत उत्पन्न हुए। जिससे स्वतंत्र उत्पादन को प्रोत्साहन मिला (व्यक्तिगतवाद को बढ़ावा मिला)।
- दूसरी ओर जहाँ महिलाएँ शिक्षित एवं कुशल नहीं थीं उनकी पति पर निर्भरता और अधिक बढ़ी।
- युवा रोजगार एवं शैक्षिक अवसरों की तलाश में शहरों की तरफ आकर्षिक हुए।
- बाजार द्वारा ऋण आदि क्षेत्रों में परिवारों की भूमिका नगण्य हो गई।

वैश्वीकरण का पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव-

- रोजगार एवं शैक्षिक अवसरों की तलाश में प्रायः लोग अपने घरों/ परिवार से दूर जाने लगे जिससे लोगों का पारिवारिक संपर्क कम होने लगा तथा संबंधों में गिरावट आयी।
- युवा वर्ग द्वारा शहरों में अपने पंसद से विवाह करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई तथा 'लिव-इन-रिलेशनशिप' जैसे नए संबंध सामने आए।
- लिंग-भेद मुक्त रोजगार के अवसरों ने महिलाओं की पुरूष पर आर्थिक निर्भरता को कम किया। जिससे परिवार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। (लैंगिक समानता आर्थिक दृष्टि से)
- महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि तथा उपभोक्तावाद की वजह तलाक देने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा विवाह संस्था के स्वरूप में परिवर्तन (विवाह अस्थायी)।
- परिवार के सदस्यों के बीच भौतिक दूरी तथा उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से संयुक्त परिवार 'एकल परिवार' में बदलने लगा।
- एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति से वृद्धों के देखभाल की चुनौती उत्पन्न हुई।
- परिवार के स्त्री-पुरूष सदस्यों द्वारा अपने काम में अधिक व्यस्तता के कारण एक-दूसरे को समय न दे पाने तथा पश्चिमी संस्कृति (सोशल मीडिया) के आकर्षण/प्रभाव के कारण 'एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स' जैसे मुद्दे उभरे।

वैश्वीकरण के भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभावों को नैतिक शिक्षा द्वारा नियंत्रित किया जाए तथा अपने संस्कृति के अच्छे मूल्यों यथा-श्री अब्दुल कलाम के शब्दों में गुरूजन एवं माता-पिता की भूमिका परिवार में अति महत्वपूर्ण होती है, का परिरक्षण किया जाए।

2. 'भारत में बढ़ती गरीबी पर नियंत्रण पाने का एकमात्र तरीका जनसंख्या को नियंत्रित करना है।' उपयुक्त उदाहरणों के साथ तार्किक दलील दीजिए।

उत्तर:

2019 के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचंकाक में बताया गया है कि भारत ने 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। लेकिन इसकी तुलना 2020 की स्थिति से करे तो भारत में सबसे अधिक गरीबी में वृद्धि हुई है।

तीव्र जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने (2019 में देश में गरीबों की संख्या 364 मिलियन थी)कुल जनसंख्या का 28: गरीब होने का अनुमान लगाया है और संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या, अनुमानों के अनुसार 2021 से 2031 के बीच भारत की जनसंख्या में 109: की गुणात्मक वृद्धि होगी जिससे निश्चित रूप से गरीबों की संख्या में वृद्धि होगी।

अधिक जनसंख्या वृद्धि गरीबी निवारण को निम्नलिखित तरीके से बाधित करती है -

- **महिला सशक्तिकरण में बाधा** - अधिक जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य हैं कि महिलाओं को अधिक बच्चे होना, जो विरोधरूप से विकासशील देशों में महिलाओं और बच्चों की मृत्यु या जन्म संबंधी समस्याओं की संभावना को बढ़ाता है। अनचाहे अधिक बच्चों का होना, महिलाओं के गरीबी निवारण और उनके स्वालम्बीकरण की संभावना को कम करता है क्योंकि यह उनके शिक्षा, ज्ञान, कौशल हाशिल करने की संभावना को कम करता है। जोकि उनके अर्जन क्षमता एवं स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए आवश्यक है।
- **पारिवारिक व्यय को सीमित करके** - उच्च प्रजनन दर और

तीव्र जनसंख्या वृद्धि पारिवारिक संसाधनों को न केवल तेजी से कम करता है बल्कि संसाधनो के लिए दूसरों पर निर्भरता को बढ़ाता है, इसके परिणामस्वरूप परिवार के स्वास्थ एवं शिक्षा पर कम व्यय होता है जिससे बच्चों के विकास एवं उत्पादन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- **सरकारी संसाधनों का पूर्नवितरण** - तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सरकार की उत्पादक कार्यो में व्यय करने की क्षमता को कम कर सकती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि सरकार को अपने संसाधनों को गरी. बों, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ एवं देखभाल पर व्यय करने के लिए बाध्य करता है जिसके कारण अन्य विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नही हो पाते।
- **मजदूरी एवं रोजगार संभावना को कम करके** - जनसंख्या वृद्धि की दर नाटकीय रूप से रोजगार सृजन की दर से बहुत अधिक है, यदि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि की दर बनी रही, तो विश्व के गरीब देशों में यदि रोजगार सृजन बहुत तेज गति से नहीं हुए तो स्थिति और भयावह हो जायेगी। अब से 2050 के बीच विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में जहाँ पहले से ही 80: कार्यशील जनसंख्या बेरोजगार है उनमे 15 मिलियन कार्यशील जनसंख्या प्रतिवर्ष और जुड़ती जायेगी।

लेकिन केवल तेजी से बढ़ती जनसंख्या को ही बढ़ती गरीबी का एकमात्र कारण नही माना जा सकता बल्कि अवसंरचना विकास में कमी, अनुपयुक्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं, भ्रष्टाचार आदि भी इसके अन्य कारक है। अतः कुशल जनंसख्या नीति, साक्षरता व जाग. रूकता, मानव संसाधन विकास और सामाजिक अवसंरचना विकास द्वारा गरीबी और जनसंख्या दोनो को नियंत्रित किया जा सकता है।

3. साम्प्रदायिक सद्भाव क्या है? देश के सामाजिक-राजनी. तिक ताने-बाने पर अशांत साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रभावों की चर्चा कीजिए।

उत्तरः

सांप्रदायिक सदभाव का अर्थ है, विभिन्न धर्मों, जातियों, पंथों, लिंग एवं विभिन्न पुष्ठभूमि के लोग समाज में एक साथ प्रेम और शांति के साथ रहते है। साम्प्रदायिक सद्भाव विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव पैदा करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में निहित या प्रेरित सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना है।

भारत एक सहिष्णु देश रहा है। वैदिक दर्शन, बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक भारतीय समाज, एक जीवन शैली के रूप में सहिष्णुता और सद्भाव के उदाहरणों से भरा है। लेकिन हाल के दिनों में पूरे देश भर में सम्प्रदायिक हिंसा में वृद्धि हुई है। इस साम्प्रदायिक वैमनस्य का कारण, वोट बैंक की राजनीति, पहचान के लिए संघर्ष, हितो का टकराव, धार्मिक विचारधाराओं पर खतरे की आशंका, मीडिया द्वारा गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग, असहिष्णुता का बढ़ता स्तर आदि हो सकता है।

सामाजिक असहिष्णुता के प्रभाव-

- असहिष्णुता और साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ने से बहुसंख्यकवाद की स्थिति पैदा होती है और इस तरह अल्पसंख्यकों का दमन होता है और उनके अधिकारों में बाधा उत्पन्न होती है।
- वैमनस्य बढ़ने से धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है और भीड़-हिंसा में वृद्धि होती है जिससे अल्पसंख्यकों का अधि कार प्रभावित होता है।
- इससे राष्ट्र विरोधी तत्वों को क्षेत्रीयता की भावनाओं को भड़काने का पर्याप्त अवसर मिलता है और हमारे समाज की एकता की भावना कमजोर होती है।
- देश में सक्रिय विघटनकारी ताकतों द्वारा साम्प्रदायिक वैमनस्य से उत्पन्न अराजकता का दुरूपयोग किया जाता है जिससे आंतरिक सुरक्षा संबधी संकट बढ़ जाता हैं।

राजनीतिक-

- साम्प्रदायिक वैमनस्य ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया है, असहिष्णुता और असामंजस्य के कारण भाषण एवं अभि. व्यक्ति की बहुत जाँच होने लगी है, और जीवन के भय के कारण कई लोग स्वतंत्र रूप से बोलने में हिचकने लगे हैं।
- बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती से सरकारी राजस्व की हानि के साथ-साथ मानवधिकारों के उल्लंघन की भी संभावना बनी रहती है।
- भीड़ द्वारा निर्णय और लिचिंग की घटनाओं में वृद्धि से कानून के शासन के लिए खतरा उत्पन्न होता है हाल के दिनों में भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियो की हत्या कानून के शासन के समक्ष एक गंभीर खतरा है।
- इसके द्वारा युवकों को साम्प्रदायिक राजनीति की तरफ लुभाया एवं अलगावाद तथा आतंकवाद की तरफ आसानी से मोड़ा जा सकता है।

भारतीय समाज एक विकासशील समाज है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग समुदाय के अंग के बजाय एक इंसान के रूप में देखने जरूरत है, केवल यही हमारे बीच पारस्परिक सौहार्द्र बढ़ाने में मदद कर सकता है। अतः

धार्मिक सहिष्णुता की नीति, राजनीतिक संवेदनशीलता व कानून के कठोर क्रियान्वन द्वारा सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

4. जीवन के हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के लगातार बढ़ते अनुप्रयोग के साथ, इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। भारत की सामाजिक संरचना पर इंटरनेट की पहुंच के प्रभावों की विवेचना कीजिए।

उत्तरः

आईएएमएआई- कांनतार आई.सी.यू.बी.ई. 2020 रिपोर्ट के अनुसार, भारत मे सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में अगले पाँच वर्षो में 45: की वृद्धि, और 2020 में लगभग 622 मिलियन से

बढ़कर 2025 तक 900 मिलियन तक पहुंच जाने की उम्मीद है। शहरी भारत मे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2020 में 4: बढ़कर 223 मिलियन हो गई है, जो कुल शहरी आबादी का 67: है। देश के शीर्ष नौ शहरों में शहरी भारत के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 33: हिस्सा है।

कई अध्ययनों मे यह पाया गया है कि समग्र निवेश, शिक्षा, ऊर्जा और परिवहन नेटवर्क जैसे सुविधाओं के साथ दूरसंचार

सुविधा आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कारकों मे से एक है। लेकिन हर तकनीक का अपना सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव भी होता है।

भारत की सामाजिक संरचना पर इंटरनेट पहुंच का प्रभाव-

सकारात्मक-

- समाज का कमजोर तबका अब अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक हुआ है और आसानी से अपनी शिकायतों का समाधान करने के लिए इस साधन का उपयोग कर सकता है।
- कोविड 19 का अनुभव हमें बताता है कि कैसे इंटरनेट ने हमें अपने स्वजनों के साथ संपर्क स्थापित करने में पूर्ण लॉकडाउन के समय में भी मदद की।
- इंटरनेट ने समाज के आश्रित वर्ग के लोगों को आजीविका एवं नये अवसरों के लिए एक मंच प्रदान किया है।
- इसने आमाजिक पूर्वाग्रहों तथा किसी भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर प्रदान करके समाज के उन वर्गो को मुक्त किया है जो सामाजिक जकड़न के शिकार थे।
- इसने आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनने में सहायता की है और साथ ही इसने बुजुर्गो में नए अभिरूचियों एवं शौक विकसित करने में मदद की है।
- महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आज पहले की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक जागरूक हुए है।
- इंटरनेट ने सेवाओं को हमारे दरवाजें पहुंचाने में मदद की है और सरकार को अपनी सेवाओं को हर लभार्थी एवं हर जगह तक पहुंचाने में मददगार सफल हुई है।

नकारात्मक प्रभाव-

- इंटरनेट ने समाज में एक डिजिटल विभाजन पैदा किया है जो तकनीकी पहुँच के आधार पर समाज को वर्गो में विभाजित करता है।
- इसने गलत सूचनाओं के अनियंत्रित प्रवाह और घृणा के कारण भय और खतरे का वातावरण तैयार हुआ है।
- समाज के एक बहुत बड़े तबके को हैकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बना लेते हैं।
- आज विभिन्न वेबसाइटें अश्लील सामाग्री और नग्नता से भरी हुई है जो बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं।
- महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इन्हे ऑनलाइन माध्यमों से परेशान किया जाता है।
- ऑनलाइन अपराध जैसे- (हैकिंग, डाटा चोरी, निजता का उल्लंघन, साइबर बुलिंग) तेजी से बढ़ रहे हैं, और बुजुर्ग तथा कम पढ़े-लिखे लोग इसके मुख्य शिकार हो रहे है।
- बच्चे मैदान पर खेलने या अपने वास्तविक जीवन के दोस्तों के बीच रहने के बजाय इंटरनेट पर अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम की लत एक गंभीर समस्या बनती जा रही हैं।

इंटरनेट ने लोगों के जीवन को बेहतर तरीके से बदला है चाहे वो व्यवसायी या उपभोक्ता या फिर टेक्नोक्रेट। इसने आर्थिक संवृद्धि, उत्पादकता, कुशलता, लाभ, रोजगार एवं बाजार आदि में बढोत्तरी की है साथ ही समय, ऊर्जा एवं धन आदि की बचत की है। लेकिन हर नई तकनीक पर उचित नियंत्रण एवं संतुलन होना चाहिए अन्यथा यह सामाजिक संरचना को प्रभावित कर सकती है।

5. बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और बढ़ते अवसरों ने भारत में बड़े पैमाने पर अंतर-राज्यीय प्रवसन को जन्म दिया है। इस प्रवसन ने क्षेत्रवाद और मूल सांस्कृतिक प्रथाओं को काफी नुकसान पहुंचाया है। परीक्षण कीजिए।

उत्तरः

प्रवासन को एक देश, क्षेत्र या निवास स्थान से दूसरे जगहों पर गमन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आज दूनिया भर में लोग बेहतर शैक्षिक एवं रोजगार के अवसरों के लिए, उत्पीड़न से बचने के लिए, आपदाओं से पीड़ित होकर, आतंकवाद या युद्ध के कारण, या पहले से प्रवासन कर चुके अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए प्रवासन को चुनते हैं।

लेकिन प्रवासन, किसी क्षेत्र की संस्कृति या व्यक्ति की सांस्कृ. तिक पहचान को गहरे रूप में प्रभावित करता है। अप्रवासियों द्वारा आत्मसातीकरण करने में मनोसामाजिक परिवर्तनों का अनुभव किया जाता है। इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसके द्वारा सांस्कृतिक विभिन्नता खत्म हो जाते है क्योंकि अप्रवासी समुदाय द्वारा बहुसंख्यक या मेजबान संस्कृति और मूल्यों को अपना लिया जाता है। आत्मसात की प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान विलुप्त हो सकती है क्योंकि वह मेजबान समाज रहता है। सांस्कृतिक संक्रमण की प्रक्रिया जो स्वैच्छिक या दबाव से हो सकती के लिए विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच संपर्क की आवश्यकता होती है, इसके परिणामस्वरूप बहुसंख्यक समुदाय के भीतर, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा उनके सांस्कृतिक मूल्यों, रीति-रिवाजों, विश्वासों और भाषा को आत्मसात किया जाता है। संस्कृतिकरण प्रक्रिया के दौरान, अप्रवासी और मेजबान दोनों संस्कृतियाँ परिवर्तित हो सकती हैं।

अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक संस्कृतियों के परस्पर अंत:क्रिया से दोनों के दृष्टिकोण, पारिवारिक मूल्य पीढ़ीगत स्थिति और सामाजिक संबद्धता में परिवर्तन हो सकता है। यद्यपि, आमतौर पर इस प्रक्रिया में एक संस्कृति प्रभावी होती है।

आबादी के पलायन के कारण क्षेत्रवाद भी अपना महत्व खो रहा है। इसके अलावा, यदि व्यक्ति अपनी संस्कृति से अलग-अलग महसूस करता है, बहुसंख्यक संस्कृति द्वारा अस्वीकार्य किया जाता है और उसे सामाजिक सर्मथन भी नही है तो ऐसे में उसमें अस्वीकृति,

अलगाव, और आत्म सम्मान की कमी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है।

लेकिन दूसरी तरफ प्रवास का सकारात्मक पक्ष यह है कि इसने विकसित देशों की संस्कृतियों, नृजातीयता और नस्लीय विविधता को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। विभिन्न संस्कृति बनाते है जिसमें प्रत्येक समूह समान रूप से भागीदार होता है। मिश्रित संस्कृति की यह सुन्दरता प्रवासन के कारण ही है। इसलिए प्रवासन हमेशा एक खतरा नहीं होता, बल्कि यह हमेशा बदले में कुछ न कुछ देता रहता है।

6. हाल ही में, कई भारतीय राज्यों ने अपने शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी को प्राथमिक भाषा घोषित करने के कदम का विरोध किया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय एकता में भाषा की भूमिका पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।

उत्तर:

भारतीय संविधान देश की 22 प्रमुख भाषाओं को अधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करता है जिसमें केन्द्रीय स्तर पर भारत भर में संघर्ष स्थापित करने के लिए देवनागरी लिपि के साथ हिन्दी को ''अधि कारिक भाषा'' के रूप में मान्यता प्राप्त है।

हिन्दी का भारत की 'राष्ट्रीय भाषा' होने की बहस तब से चल रही है जब संविधान लिखा जा रहा था। इसे हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे द्वारा पुर्नजीवित किया गया जो अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिन्दी को अधिक महत्व देता है। वास्तव में, भारत में देशज हिन्दी बोलने वालों की संख्या केवल 44: है, जिसमे भोजपुरी जैसी भाषाओं को बोलने वाले भी शामिल है। हिन्दी राष्ट्रीय पहचान व एकीकरण एक माध्यम हो सकता है क्योंकि लगभग आधी आबादी द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा एक भाषा के द्वारा राष्ट्रीयता के निर्माण को मजबूती प्राप्त होती है।

एक राष्ट्रीय भाषा या किसी भाषा के 'थोपने' संबधित मुद्दों के बारे में लोगों द्वारा बहुत गहराई से महसूस होने का एक कारण यह है कि भाषा किसी व्यक्ति की पहचान की मूल तत्व होती है। भाषा ही वह माध्यम है जिसमे व्यक्ति

अवधारणाएं बनाता है और अपने विचारों को संम्प्रेषित करता है, यही उसे समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाता है।

भाषा से संबंधित कई नीतियां केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई हैं जिन्हें भाषाई अंधश्रद्धा का नाम दिया गया है। ऐसी नी. तियों से भारत की विविधता और संघवाद को खतरा है। केन्द्र सरकार की आस्था, शिक्षा और भाषा पर एकाधिकार रखने की विचारधारा से राज्यों का डर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो कि बहुलवाद और समझौता पर आधारित है। केन्द्र और राज्यों की नीतियों को सावधानी से देखा चाहिए क्योंकि वे बहुसंख्यकवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं।

राष्ट्रीय एकता की भावना लोगों की भाषाई पहचान की कीमत पर नहीं आ सकती। एक बहुभाषी देश में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, एक आधिकारिक भाषा को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती, विशेषकर जब इस उदेश्य के लिए चुनी गई भाषा अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं में से एक हो, भले ही वह देश का सबसे बड़ा भाषाई समूह ही क्यों न हो। साथ ही एक समय मे, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और यहाँ तक सामाजिक विषयों पर केन्द्र-राज्य और अंतर राज्य संपर्क के लिए एक या अधिक आधिकारिक भाषा या भाषाओं के होने की सुविधा या आवश्यकता पर विवाद नही किया जा सकता।

7. भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

उत्तर:

भारतीय संस्कृति की बहुलता और विविधता पूरी दुनिया में स्पष्ट है क्योंकि भारत में संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोकपरंपराओं, प्रर्दशन कलाओं, संस्कारो एवं अनुष्ठानों, भाषाओं एवं बोलियों, चित्र एवं लेखन, भवन, मन्दिर, स्तूप आदि का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है जिसे मानवता की अमूर्त व मूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का राष्ट्रीय महत्व होता है और ये सांस्कृ. तिक ज्ञान के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण होते है इसलिए इन्हे निम्न तरीके से संरक्षित करने की आवश्यकता है-

- संस्कृति मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने की एक परियोजना प्रारम्भ की है जिसका उद्देश्य विभिन्न संस्थानों, समूहों, व्यक्तियों, स्वयं सेवी संगठनों एवं शोधकर्ता, बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने, सुरक्षित एवं संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने जैसी परियोजनाओं एवं गतिविधियों में उत्साह के साथ सम्मिलित हो सकें।
- इसके अलावा, भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में, 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को सफलतापूर्वक शामिल कराया है।
- साथ ही, भारत की अमूर्त विरासत की राष्ट्रीय सूची, इसकी अमूर्त विरासत में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विभिन्न राज्यों के विविध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- विरासत स्थलों, स्मारकों, खंडहरों को विकसित करने और उन्हे पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए 27 सितम्बर 2017 में ''एक विरासत अपनाएं'' योजना शुरू की गई। परियोजना का उद्देश्य नियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से पर्यटन संभावना और विरासत के सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना है।
- भवन एवं स्थापत्य विरासत लोगों में जागरूकता के अभाव तथा प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के कारण दुष्प्रभावित हो रहा है जिसे प्रशासनिक संवेदनशीलता, जागरूकता के प्रसार व वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।

भारतीय पारम्परिक कला एवं शिल्प को पूरे भारत में सदियों से विभि.

ान्न शिल्प संघों द्वारा विकसित किया गया है। यद्यपि वे सदियों से देश के सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करती रही है लेकिन देश की एक बड़ी आबादी एवं शिल्प संघों का इससे क्रमिक अलगाव देश की सांस्कृतिक जीवंतता को प्रभावित करेगा। इसलिए इसके संरक्षण के लिए नए तरीकों की जरूरत है।

8. भारतीय चित्रकला में मुगल काल के योगदान की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

मुगल काल में बनाए गये चित्रों की अपनी एक विशिष्ट शैली थी, जो कि फारसी पृष्ठभूमि से प्रभावित थी। वहाँ का रंग मिश्रण, विषय एवं रूप भिन्न था। मुगलकाल में चित्रण का विषय धार्मिक से हटकर शासक का महिमामण्डन एवं उसके जीवन को प्रदर्शित करना हो गया। इस समय अधिकांशतः शिकार के दृश्यों, ऐतिहासकि घटनाओं एवं अन्य दरबारी गतिविधियों को चित्रित करना प्रारम्भ हुआ।

प्रमुख योगदान-

- मुगलों ने भारतीय चित्रकारों को पूर्वाभास तकनीक से परिचित कराया। इस तकनीक में वस्तुओं को इस तरह चित्रित किया गया कि चित्र में ये अपने वास्तविक रूप की तुलना में नजदीक एवं छोटे दिखते हैं।
- बाबर ने बिहजाद को संरक्षण प्रदान किया उसके पश्चात् हुमाँयू ने अपने समय के विख्यात चित्रकार अब्दुस्समद एवं मीर सैय्यद अली को हेरात से लाकर उन्हें संरक्षण प्रदान कर मुगल शैली की नींव रखी।
- अकबर ने ग्रन्थ चित्रण एवं सुलेखन के लिए दरोगा नामक अधिकारी के नेतृत्व में एक अलग चित्रशाला विभाग की स्थापना की।
- भारतीय विशेषताओं के साथ त्रिआयामी चित्रण अकबरकालीन चित्रकारी की प्रमुख विशेषता है।
- जहाँगीर के समय में मुगल चित्रकला का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई। इस काल मे प्रकृति चित्रण पर बहुत जोर दिया गया। जहाँगीर काल के चित्रों की एक अन्य विशेषता विकसित हुई जिसमें चित्रों को सजावटी हासियें से सजाया जाने लगा।
- शाहजहाँ ने चित्रों को आकर्षक बनाने के लिए कलाकारों को रेखाकंन के लिए चारकोल की जगह पेंसिल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। शाहजहाँ ने चित्रों को भड़कीला बनाने के लिए सोने एवं चाँदी के उपयोग को प्रोत्साहित किया।
- मुगलों की चित्रकला के विकास में एक महत्वपूर्ण देन 'सूक्ष्म चित्रकारी' है।

इस प्रकार मुगल शैली की सुदृढ़ एवं सुन्दर पृष्ठभूमि के ने राजपूत शैली, पहाड़ी शैली आदि को व्यापक रूप से प्रभावित एवं विकसित करते हुए भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा दी।

9. 'स्वतंत्रता के बाद, भारत का एकीकरण कई कठिनाइयों से भरी एक चुनौती थी'। विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थीं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लैप्स ऑफ पैरामाउंट्सी (सर्वोच्चता की समाप्ति) की घोषणा के पश्चात् इन रियासतों के समक्ष तीन विकल्प थे, ये भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थीं या स्वतंत्र रह सकती थीं। इन देशी रियासतों का भारत में एकीकरण भारत के भविष्य, एकता और अखंडता के लिए आवश्यक था किन्तु इनके एकीकरण में विभिन्न चुनौतियाँ थीं जो निम्नलिखित हैं-

- लगभग 565 रियासतों का एकीकरण करना था जिनमें अधिकतर छोटी-छोटी रियासतें थीं। इसने समझौता प्रक्रिया को कठिन बना दिया था।
- मुस्लिम लीग भी अधिकतम राज्यों को तोड़कर पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास कर रही थी (जैसे- जूनागढ़, जोधपुर इत्यादि)।
- राज्य की जनता व शासकों के बीच मतभेद भी था, जैसे- जम्मू-कश्मीर व हैदराबाद। अधिकतर मामलों में जनता भारत में विलय चाहती थी पर उनके शासक पाकिस्तान में मिलना चाहते थे।
- कुछ रियासतों जैसे त्रावनकोर व हैदराबाद आदि ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की। यह भारतीय एकता, इन रियासतों की जनता के स्वनिर्धारण तथा इन राज्यों में लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न कर सकता था क्योंकि अंतिम निर्णय इन राज्यों के शासकों द्वारा लेना था, न कि इसकी जनता द्वारा।
- विभाजन की पृष्ठभूमि में क्षेत्रों के सीमांकन पर भी विवाद था।
- उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर जैसी रियासतों की भौगोलिक स्थिति ने भी विशेष संवेदनशीलता को बढ़ाया।

भारत सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए तीन विचारों पर ध्यान दिया-

- बहुलता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्ता देने के लिए तैयार थी।
- अधिकतम लोग भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे।
- क्षेत्रीय सीमाओं के एकीकरण व संगठन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

इन आधारों पर अधिकतम रियासतों से शांतिपूर्ण समझौते द्वारा 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर कराया गया। फिर भी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर तथा मणिपुर की रियासतों के एकीकरण को अलग प्रकार से किया गया।

- हैदराबादः निजाम अपने अर्द्धसैनिक बलों रजाकारों द्वारा भारत की तरफ वाली जनता को कुचलना चाहता था। तब भारतीय सरकार को जनता को बचाने व निजाम के आत्म समर्पण हेतु बल का प्रयोग करना पड़ा।
- मणिपुरः मणिपुर की जनता भारत में विलय बनाम संवैधानिक राजतंत्र के विषय पर विभाजित थी। भारत सरकार ने दबाव बनाकर बिना विधान सभा से सलाह किये राजा से समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिया। इससे लोगों में रोष उत्पन्न हुआ जिसे आज भी देखा जा सकता है।

विभिन्न कूटनीतिक प्रयासों एवं बल प्रयोग द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। हाल ही में धारा 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को पूर्णतः भारतीय संविधान के अधीन लाया गया। जिससे भौगोलिक एकीकरण की संकल्पना साकार हुई परंतु हमें भारत को एक वास्तविक राष्ट्र बनाने के लिए भौगोलिक एकीकरण से मानसिक एकीकरण की ओर जाना होगा।

10. 'सत्याग्रह' से आप क्या समझते हैं? भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रक्रिया में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तरः

'सत्याग्रह' का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के साथ बने रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति बैरभाव न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है।

सत्याग्रह का विचार मूलरूप से सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर जोर देता है। यह कहा जाता है कि यदि कारण सत्य है, यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए शा. रीरिक बल आवश्यक नहीं हैं। आक्रामक हुए बिना, एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से लड़ाई जीत सकता है, यह उत्पीड़क की अन्तर्आत्मा को प्रभावित करके किया जा सकता है। आम लोगों, यहाँ तक कि उत्पीड़क को सत्य के बारे में समझाकर किया जा सकता है, न कि इसे हिंसा के बल पर सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करके। इस विशाल और महान संघर्ष से अंततः सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म ही सभी भारतीयों को एकजुट कर सकती है।

सत्याग्रह का भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रक्रिया में महत्व-
सत्याग्रह को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए आत्मिक शक्ति का हथियार माना जाता था। जबकि गांधी ने सत्याग्रह को जीवन का एक तरीका माना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, सत्याग्रह को राज्य के अधिकार का विरोध करने और लोगों के सामान्य कल्याण के लिए विभिन्न चीजों को प्राप्त करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने न केवल लोगों के लिए भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण अधि कार का विरोध करने के लिए भी चंपारण और बारदोली में सत्याग्रह किए थे। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दांडी में नमक कानून को तोड़ने के साथ शुरू हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन उत्कृष्ट उदाहरण थे जब गांधी और उनके सहयोगियों ने सत्याग्रह को आत्मशक्ति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था।विभिन्न अवस. रों पर, गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध की तुलना में अधिक गतिशील शक्ति है क्योंकि यह अन्याय के प्रतिरोध में लंबे समय तक चलने वाली सामूहिक कार्रवाई पर विचार करता है। दूसरे, सत्याग्रह का अभ्यास घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर किया जा सकता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार राजनीतिक स्तर पर ही किया जाता है। तीसरा, सत्याग्रह मन की निरंतर शुद्धि प्रदान करता है। इसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध शत्रु के प्रति आंतरिक हिंसा के अनुकूल हो सकता है। सत्याग्रह की प्रथा ने ब्रिटिश उत्पीड़कों को चकित कर दिया क्योंकि हिंसा के प्रति सत्याग्रहियों की निष्क्रियता उनके द्वारा पहले कभी नहीं देखी गई थी। सत्याग्रहियों की सत्यता और अहिंसा ने अंततः उपनिवेशवादियों को स्वतंत्रता सेनानियों की दृढ़ इच्छा को समझने के लिए प्रेरित किया। सत्याग्रह युद्ध का नैतिक विकल्प है। गांधी ने हमें सूक्ष्म स्तर से वृहद स्तर तक समस्या-समाधान और संघर्ष-समाधान के लिए इसका उपयोग करने का तरीका दिखाया। गांधी का सत्याग्रह राजनीतिक समस्या निवारण का एक प्रभावी साधन साबित हुआ। युद्ध और शांति, आतंकवाद, मानवाधिकार, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक-राजनीतिक अशांति और राजनीतिक-प्रशासनिक भ्रष्टाचार से संबंधित कई समकालीन चुनौतियों का सामना गांधीवादी तरीके से किया जा सकता है। इक्कीसवीं सदी की दुनिया को इससे बहुत कुछ सीखना है।

11. सविनय अवज्ञा आंदोलन एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। इसकी उपलब्धियों और सीमाओं की चर्चा कीजिए।

उत्तरः

1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने का
अधिकार दिया था। कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गाँधी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी गई। गाँधीजी आन्दोलन करने से पूर्व वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग-पत्र रखा जिसके न स्वीकार करने पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हुआ।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के तहत महात्मा गाँधी ने 12 मार्च, 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरूआत की।

- गाँधी जी ने साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) से अपने 78 अनुयायियों के साथ ''दांडी मार्च'' शुरू किया।
- 25 दिन की 241 मील लम्बी पैदल यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी (नौसारी जिला गुजरात) पहुँचकर

गाँधी जी सांकेतिक रूप में एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हुआ।

आन्दोलन की उपलब्धियाँ :-

- सविनय अवज्ञा आन्दोलन की वजह से महात्मा गांधी ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। इस आंदोलन को यूरोपीय और अमेरिकी समाचार पत्रों द्वारा कवर किया गया।
- यह आन्दोलन पुरषों तक ही सीमित नहीं रहा। यह पहला राष्ट्रवादी गतिविधि था, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चटट्रोपाध्याय के नेतृत्व

में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।

- आन्दोलनकारियों ने नमक और शराब कानून तोड़कर गिरफ्तारी दी, हजारों विद्यार्थीयों ने स्कूल, कॉलेज छोड़ दिये, अनेकों ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, सरकारी दुकानों पर धरना दिये गये।
- गाँधी जी की गिरफ्तारी से आन्दोलन दबने की अपेक्षा और अधिक भड़क उठा। चटगाँव शस्त्रागार पर सूर्यसेन एवं उनके साथियों ने अधिकार कर लिया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में गढ़वाली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया।
- बिहार में चौकीदारी टैक्स न देने की आवाज उठी। इसी समय मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कड़े वन नियमों विरूद्ध 'वन सत्याग्रह' चलाया गया।
- इस विद्रोह के सार्थक प्रयास से सरकार गाँधी और कांग्रेस के महत्व को समझने पर बाध्य हो गयी। वह समझ गयी कि आन्दोलन को सिर्फ ताकत के बल पर ही नहीं दबाया जा सकता है। अतः संवैधानिक सुधारों की बात सोची जाने लगी।

आन्दोलन की विफलताः-

- सविनय अवज्ञा आन्दोलन की एक नई और उल्लेखनीय विशेषता महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी। हांलाकि राजनीति में महिलाओं की इस अचानक सक्रिय भूमिका से परिवार के भीतर या बाहर मf. हलाओं की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नही हुआ।
- आरम्भ में सरकार ने आन्दोलन को गंम्भीरतापूर्वक नही लिया एवं इसकी उपेक्षा की, परन्तु शीघ्र ही स्थिति की भीषणता उसे आभास हुआ।
- ब्रिटिश सरकार ने इस आन्दोलन को नृशंसतापूर्वक दबाने का प्रयास किया। सत्याग्रहियों को पकड़-पकड़कर जेलों में भरा गया। अनेक व्यक्तियों को सेना और पुलिस ने गोली मार दी। कांग्रेस को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया।
- भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू की मौत की सजा माफ करने के गाँधी जी के अनुरोध को वायसराय ने ठुकरा दिया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गयी।
- सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी न होने के कारण यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा।

गाँधी जी ने बदलती परिस्थितियों में 'व्यक्तिगत अवज्ञा आन्दोलन' की योजना बनाई, लेकिन सरकार के 'साम्प्रदायिक निर्णय' से वे हतोत्साहित हो उठे। फलतः मई 1933 में आन्दोलन को कांग्रेस ने स्थगित कर दिया तथा मई 1934 में इसे वापस ले लिया। सारे देश में उल्लास की जगह निराशा छा गई। गाँधी जी पुनः राजनीति से कटकर हरिजनों की तरफ अपना ध्यान देने लगे।

12. 'औपनिवेशिक काल के दौरान प्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई'। चर्चा कीजिए।

उत्तरः

यद्यपि कि यूरोप में अखबारों का प्रकाशन 16वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था, लेकिन छपाई और इससे जुड़े पेशे भारतीय उप-महाद्वीप में देर से पहुँचे। भारतीय उप-महाद्वीप में, 18वीं सदी के अंत में, पहले समाचार पत्र की शुरूआत, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बंगाल गजट से हुई।

18वी शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न हित समूहों के भारतीय समा. चार पत्रों का तेजी से विकास हुआ। इन वर्षो के दौरान प्रतिष्ठित एवं निर्भिक पत्रकारों के नेतृत्व में कई समाचार पत्रों का उदय हुआ। इनमें जी सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व मे 'द हिन्दू' और 'स्वदेश मित्र', सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 'द बंगाली' दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में 'द वायस ऑफ इण्डिया', शिशिर कुमार घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका और एन.एन.सेन के नेतृत्व में इण्डियन मिरर शामिल थे। बाल
गंगाधर तिलक के नेतृत्व मे 'मराठा' (अंग्रेजी) 'केशरी' (मराठी), गोपाल कृष्ण खोखले द्वारा शुरू किए गये 'सुधारक' जी0टी0 वर्मा के नेतृत्व में 'हिन्दूस्तान' और 'एडवोकेट' प्रमुख अखबार थे।

इन समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना था। वास्तव में इन समाचारपत्रों की पहुँच व्यापक थी और ये पुस्तकालय आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भू. मिका निभाई। इन आन्दोलनों का प्रभाव केवल शहरों एवं कस्बों तक ही सीमित नहीं था बल्कि ये समाचार पत्र सुदूर गाँवों में भी पहुँचे, जहाँ प्रत्येक समाचार और संपादकीय अंशो को स्थानीय पुस्तकालयों में पढ़ा और चर्चा किया जाता था। इन समाचार पत्रों में सरकारी कार्यो और नीतियों की गहन छानबीन की जाती थी, इन्होने सरकार विरोधी संस्था के रूप में कार्य किया। कानूनी बाधाओं से बचने के लिए पत्रकारों ने एक-चतुर रणनीति विकसित की। उदाहरण के लिए सरकार विरोधी अंशो के साथ सरकार समर्पित प्राक्थन भी लिखे जाते थे साथ ही इण्लैण्ड के अखबारो मे छपे आइरिश राष्ट्रवादियों एवं समाजवादियों के आलोचनात्मक अंशों का भी उल्लेख किया जाता था। यह एक कठिन कार्य था जिसमे सरलता के साथ सुक्ष्म बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी।

समय बीतने के साथ, कई अखबारो ने, राष्ट्रीय स्तर पर आम लोगों के विद्रोह के प्रयास को कुंद करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम विवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अग्रेजो की रणनीति पर ध्यान देना शुरू किया। 'तिलक' के 'केसरी' और 'मराठा' माध्यम से जनता के बीच साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहित किया गया। कई अन्य नेताओं ने
विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहित किया। कई अन्य नेताओं ने अपने अखबारों का प्रयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जैसे-

- धार्मिक पुर्नरूत्थानवाद।
- ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करना।
- भारतीय समाज पर ब्रिटिश कानूनों के प्रभावों का उल्लेख करना।
- कठिन समय के दौरान युवाओं और अन्य लोगों को उनकी भूमिका बताना।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 'ग्लोबल विंड डे' कब मनाया जाता है?
(a) 2 फरवरी
(b) 21 मार्च
(c) 5 जून
(d) 15 जून
उत्तर - D

2. निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लान्च किया है?
(a) उत्तर प्रदेश
(b) पंजाब
(c) दिल्ली
(d) केरल
उत्तर - D

3. हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्स्प्लोरर को बंद कर दिया है ?
(a) 27 साल
(b) 28 साल
(c) 30 साल
(d) 32 साल
उत्तर- A

4. विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-
1. इसे प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।
2. डेनमार्क पिछले साल के तीसरे स्थान से इस इस बार पहले स्थान पर पहुँचा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा से कथन सही नहीं है/ हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2
उत्तर- C

5. जून 2022 में एशिया के सबसे लंबे दांत वाला हाथी 'भोगेश्वर' का निधन कहाँ हुआ है?
(a) कर्नाटक
(b) केरल
(c) आन्ध्रप्रदेश
(d) झारखण्ड
उत्तर - A

6. युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें-
1. इसका आयोजन मिस्र में किया गया है.
2. नागालैंड की लोकसभा संसद सदस्य एस फांगोन कोन्याक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा से कथन सही नहीं है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2
उत्तर - B

7. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है?
(a) हैदराबाद
(b) लखनऊ
(c) बेंगलुरु
(d) मुम्बई
उत्तर - C

8. हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है?
(a) अमेरिका का पश्चिमी तट
(b) पूर्वी चीन सागर
(c) मैक्सिको की खाड़ी
(d) शार्क बे ऑस्ट्रेलिया
उत्तर - D

9. विश्व मरुस्थलीकरण और सुखा रोकथाम दिवस का आयोजन के सम्बंध में निम्न कथनों पर विचार करें-
1. इसका आयोजन 17 जून, को किया जाता है।
2. इस वर्ष की थीम "एक साथ सूखे से निपटना" है।
3. इस दिवस को 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
निम्नलिखिल कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर- D

10. हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है?
(a) तमिलनाडु
(b) केरल
(c) उत्तर प्रदेश
(d) हिमाचल प्रदेश
उत्तर - D

11. भारतीये मगरमच्छ के संबन्ध में निम्न कथन का पर विचार करें-
1. 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है।
2. 'केन्द्रपाड़ा' ओडिशा में मगरमच्छ की केवल 2 प्रजातियां पायी जाती है।
3. खारे पानी के मगरमच्छ को आईयूसीएन की "कम चिंतनीय श्रेणी" में सूचीबद्ध किया गया हैं।
निम्नलिखिल कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर - C

12. फीफा ने U-17 महिला विश्वकप 2022 का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है?
(a) भारत
(b) चीन
(c) मलेशिया
(d) ऑस्ट्रेलिया
उत्तर - A

13. संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर प्रस्ताव को निम्न में से किस देश ने प्रस्तुत किया है?
(a) भारत
(b) चीन
(c) मिस्र
(d) अंडोरा
उत्तर - D

14. बिम्सटेक के संबन्ध में निम्न कथनो का पर विचार करें-
1. बिम्सटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो, श्रीलंका में की जाएगी।
2. यह उप-क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था।
3. बिम्सटेक दक्षिण एशिया के देशों एक क्षेत्रीय संगठन है।
निम्नलिखिल कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर - A

15. ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन जो सुर्खियों में रही है, किस देश में संबंधित है?
(a) पुर्तगाल
(b) रूस
(c) चीन
(d) तुर्की
उत्तर - D

16. विश्व संगीत दिवस के संबन्ध में निम्न कथन का पर विचार करें-
1. विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को संगीत के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है।
2. इसके मनाने की शुरुआत 1982 में भारत में हुई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2
उत्तर - A

17. हाल ही में खबरों में रहा 'ओपरेशन संकल्प' किस सशस्त्र बल से संबंधित है?
(a) भारतीय नौसेना
(b) भारतीय थल सेना
(c) भारतीय वायु सेना
(d) अर्धसैनिक बलों
उत्तर - A

18. हाल ही में फातिमा पेमान किस देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनीं है?
(a) फ्रांस
(b) पाकिस्तान
(c) तुर्की
(d) ऑस्ट्रेलिया
उत्तर - D

व्यक्ति विशेष : श्यामा प्रसाद मुखर्जी

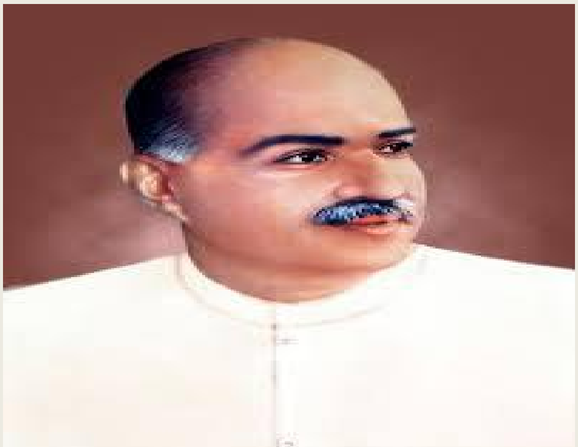

श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान नेतृत्व और राजनीतिक उदीयमान सूर्य के उदाहरण हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद एक योग्य बैरिस्टर थे और शिक्षा के प्रति गहरी रूचि रखते थे।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में

1. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई , 1901 को हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

2. उन्होंने 1906 में भवानीपुर के मित्र संस्थान में अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरम्भ की। उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रेसीडेंसी कॉलेज में भर्ती हुए।

3. वे 1916 में इंटर-आर्ट्स परीक्षा में सत्रहवें स्थान पर रहे और 1921 में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल करते हुए अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

4. 1924 में उनके पिता का देहांत हो गया, उसी वर्ष उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में नामांकन किया।

5. 33 साल की उम्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने।

6. कुलपति के रूप में मुखर्जी के कार्यकाल के समय, रवींद्रनाथ टैगोर ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को पहली बार बंगाली में संबोधित किया और भारतीय भाषा को सर्वोच्च परीक्षा के लिए एक विषय के रूप में शुरू किया गया।

7. मुखर्जी ने 1946 में मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों को न शामिल करने हेतु बंगाल के विभाजन की मांग की। 15 अप्रैल, 1947 को तारकेश्वर में हिन्दू महासभा द्वारा आयोजित एक बैठक ने उन्हें बंगाल के विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने हेतु अधिकृत किया।

8. मई 1947 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र लिखकर कहा था कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए, भले ही भारत न हो। उन्होंने 1947 में सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत बोस और बंगाली मुस्लिम राजनेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी द्वारा बनाई गई एक संयुक्त लेकिन स्वतंत्र बंगाल के लिए एक असफल मांग का भी विरोध किया।

9. जम्मू और कश्मीर के मुद्दों पर तत्कालीन प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू से मतभेद होने के कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दिया और वर्ष 1951 में जन संघ की स्थापना की जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। .

10. बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवेश करने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 40 दिन बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी।

NOTES

ध्येय IAS® most trusted since 2003
DHYEYA IAS® most trusted since 2003

ANNUAL SUBSCRIPTION OF PERFECT 7 CURRENT AFFAIRS MAGAZINE (FORTNIGHTLY)

About Perfect 7:

The role of Current Affairs in Civil Services has tremendously increased, in all the subjects of General Studies like Economy, Polity, Science and Technology, International Relations, Environment, etc.

Need: Knowledge of Current Affairs

Inadequate Solution: Monthly Magazines available in the Market.

Why Inadequate?

- All magazines are monthly: This means that you get to know about the event after more than one month and students are unable to match the pace with newspaper and other media.
- Not suitable for Civil Services: Events are not analyzed as these magazines also cater to the one day exams and hence they provide only factual information's.
- Too much to read in one go: A student is suddenly burdened to cover too many events in a short time which leads to stress.

Solution to all the above three issues is PERFECT 7 Magazine by Dhyeya IAS.

- Released Fortnightly: A student is abreast with the current events of the month, near real time.
- Detailed Analysis of every event: Civil Services demands a deeper understanding of events, concepts and its analyses and not just know the event and its date.
- Easy to study: Since the magazine is fortnightly, a student is saved from Information overload and can relate with the newspaper, TV and other media coverages with a profound understanding of the current happenings.

Features of PERFECT 7

Important conditions for an IAS/PCS centered magazine		PERFECT 7	OTHERS
• Fortnightly	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Civil Services Exam centered	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Micro-Analysis of current issues & not a mere compilation of facts	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Brain boosters for important issues	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Multiple choice questions & their solution based on brain boosters	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Case studies with model answers for Ethics	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Explanation of important theories through pictures & graphics.	Hindi	✓	×
	English	✓	×

(* some institutes)

Annual Subscription Fee along with Courier Charges:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Courier Charges:	30 X 24 = Rs 720
Total Charges:	**Rs 1530**

Annual Subscription Fee for Student Collecting Magazine form Mukherjee Nagar Centre:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Total Charges:	**Rs 810**

BANK ACCOUNT DETAILS

Account Holder:-	**Trueword Publication Private Limited**
Bank A/C -	**50200032675602**
IFSC:-	**HDFC0000609**

Terms and Condition:

1. Fee submitted one will not be refunded or adjusted in any condition.
2. Dhyeya IAS ensures no damage or delay during transit however some unavoidable circumstances are beyond our control. responsibility for the delay in delivery,
3. W put best efforts to make the Magazine reach to the subscribers by 10th & 25th of every month.
4. If due to COVID-19 Pandemic or any unforeseen natural disaster or by an act of God, Dhyeya IAS is not able to print the Magazine then the duration of subscription will be increased to compensate for the same.

AN INTRODUCTION

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS, two decades old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4500 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

₹ 45

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I B**hubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744